ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिवशक्ति बक्सी

संपादक मंडल

सत्यपाल

संजीव कुमार सिन्हा

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल

विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-

त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798

Qku (dk-) : +91(11) 23381428

QSDl : +91(11) 23387887

पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई–मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय-सूची

यूपीए सरकार द्वारा पेट्रोल की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि किए जाने के विरोध में भाजपा–नीत एनडीए द्वारा आहूत 'भारत बंद' के दौरान प्रदर्शन करते भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) श्री रामलाल, राष्ट्रीय महासचिव श्री अनंत कुमार एवं श्री विजय गोयल, दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता एवं पार्टी नेतागण

पेट्रोल मूल्य वृद्धि के विरोध में 'भारत बंद'

एक रिपोर्ट 6

महंगाई के खिलाफ भाजपा का जनसंघर्ष अभियान........ 11

लेख

नदियों को परस्पर जोड़ने पर सर्वोच्च न्यायालय का उत्कृष्ट निर्णय
&ykyÑ".k vkMok.kh 12

अखण्ड भारत के पुरोधा
&Mk- egs'k pUæ 'kek 15

राजनीतिक ईमानदारी पर सवाल
&cycht iqt 19

स्वच्छ दामन पर काला दाग
&,- lw;çdk'k 21

नीति, नीयत और नेतृत्व
&çk- vk'kh"k ckl 22

राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक (मुम्बई)

पवित्र गंगा की सुरक्षा और प्रदूषण मुक्ति पर वक्तव्य........ 25

श्री अरुण जेटली द्वारा राजनैतिक प्रस्ताव पर जारी वक्तव्य..... 27

भाजपा रैली........ 28

अन्य

राज्य सम्मेलन, थमरई संगमाम, मदुरई........ 24

बोध कथा

पानी की तरह

स्वामी श्रद्धानंद के शिष्य थे सदानंद। उन्होंने काफी मेहनत से विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया था। लेकिन उन्हें अपने ज्ञान पर अहंकार हो गया। धीरे–धीरे उनके व्यवहार में बदलाव आ गया। वह हर किसी को हेय दृष्टि से देखने लगे। यहां तक कि वह अपने साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे अपने मित्रों से भी दूरी बनाकर रहने लगे। वह जब भी चलते, तनकर चलते।

यह बात स्वामी जी तक भी पहुंची। पहले तो उन्हें लगा कि सदानंद के साथी ऐसे ही कह रहे हैं। हो सकता है सदानंद के किसी आचरण से इन्हें ठेस पहुंची हो। लेकिन एक दिन स्वामी जी उनके सामने से गुजरे तो सदानंद ने उन्हें अनदेखा किया और उनका अभिवादन तक नहीं किया। स्वामी जी समझ गए कि इन्हें अहंकार ने पूरी तरह जकड़ लिया है। इनका अहंकार तोड़ना आवश्यक है अन्यथा भविष्य में इन्हें दुर्दिन देखने पड़ सकते हैं। उन्होंने उसी समय सदानंद को टोकते हुए उन्हें अगले दिन अपने साथ घूमने जाने के लिए तैयार कर लिया।

अगली सुबह स्वामी जी उन्हें वन में एक झरने के पास ले गए और पूछा– पुत्र, सामने क्या देख रहे हो? सदानंद ने जवाब दिया– गुरु जी, पानी जोरों से नीचे बह रहा है और गिरकर फिर दोगुने वेग से ऊंचा उठ रहा है। स्वामी जी ने कहा– पुत्र, मैं तुम्हें यहां एक विशेष उद्देश्य से लाया था। जीवन में अगर ऊंचा उठकर आसमान छूना चाहते हो तो थोड़ा इस पानी की तरह झुकना भी सीख लो। सदानंद अपने गुरु का आशय समझ गए। उन्होंने उनसे अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी।

संकलन : मुकेश जैन

साभारः नवभारत टाईम्स

व्यंग्य चित्र

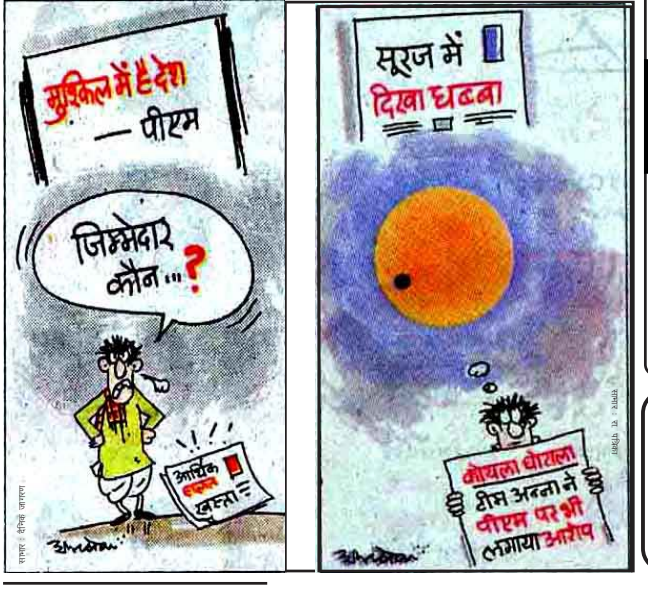

हमें लिखें...

सम्पादक के नाम पत्र

कमल संदेश

सादर आमंत्रित

आपकी राय एवं विचार

सम्पादक,
कमल संदेश
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी–66
सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003
ई-मेलः
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रिय पाठकगण

कमल संदेश (पाक्षिक) का अंक आपको नियमित मिल रहा होगा। यदि किन्हीं कारणवश आपको कोई अंक प्राप्त न हो रहा हो तो आप अपने प्रदेश कार्यालय को या हमें अवश्य सूचित करें।

-सम्पादक

सनसनी और संवेदना में अंतर समझना होगा मीडिया को

वर्ष 131 ईसा पूर्व रोम में सूचना तंत्र का प्रारंभ हुआ। पत्थरों की खुदाई होती थी और लोग चौराहों पर आकर पत्थरों पर खुदी चीजों को पढ़ते थे। संचार की दुनिया में क्रांति हुई और सेकेंड भर में खबरें छोटी हो या बड़ी विश्वभर में फैल जाती है। इसलिए चौथे स्तंभ के रूप में स्थापित मीडिया का दायित्व अन्य तीन स्तम्भों– विधायिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका से कम नहीं आंका जा सकता। अगर तीनों स्तंभ पर संविधान की जिम्मेदारी हैं तो मीडिया पर है सामाजिक जिम्मेदारी। वर्षों इस क्षेत्र में रहा हूं इसलिए सनसनी और संवेदना में अंतर समझता हूं। और यह मेरे समझने से नहीं बल्कि उन्हें समझना होगा, जिन्होंने मीडिया की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। अर्थ का अनर्थ नहीं करना चाहिए। अर्थ को समर्थ बनाना चाहिए। निश्चित तौर पर मीडिया को सरकारी नियंत्रण परिधि में नहीं रखना चाहिए पर उसे सामाजिक परिधि में जरूर रखना चाहिए। मीडिया की समाज–राष्ट्र से बड़ी अहमियत नहीं हो सकती। समाज रहेगा–देश रहेगा तो मीडिया का महत्व रहेगा। भारत एक संस्कृति प्रधान देश है। संस्कृति इसकी धरोहर है। उससे छेड़छाड़ करने का अधिकार अनधिकृत तौर पर किसी को नहीं है।

हाल ही में मुरैना में एक घटना घटी। एक दुर्घटना में आईपीएस नरेन्द्र कुमार की मृत्यु हुई। जवान आईपीएस के जाने का जितना उनके परिवार को दुख हुआ, उससे कहीं अधिक देश दुखी हुआ। आईपीएस देश का होता है, परिवार का नहीं। पर वो हत्या थी या हादसा, यह जाने बगैर जिस तरह से चैनलों में और समाचार पत्रों में राष्ट्रीय पर्व होली के दिन भारतीय मानस को बदरंग करने की कोशिश की गई और भाजपा शासित मध्यप्रदेश सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई, क्या इसे उचित माना जा सकता है? सीबीआई की रिपोर्ट आ गई। सीबीआई ने रिपोर्ट में साफ–साफ लिखा है कि नरेन्द्र कुमार की मृत्यु के पीछे न कोई खदान माफिया था और न कोई इरादतन हत्या। यानी हादसा थी। पर जिस तरह से चैनलों पर बवाल खड़ा किया और भाजपा की शिवराज सरकार को बदनाम किया गया, क्या उसकी भरपाई अब हो सकती है?

मीडिया जनमानस का मानस बनाता है। मीडिया परिवार को प्रभावित करने की स्थिति में आ चुका है। ऐसे में क्या वह अपनी जिम्मेदारी से मुकर सकता है? सत्य को सत्य के निकट जानकर तथ्यों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। मीडिया चाहे तो आस्था पैदा करवा दे और चाहे तो अनास्था पैदा करवा दे। पर जब समाज ने मीडिया पर इतना विश्वास किया है तो मीडिया को भी अपनी कार्यपद्धति पर विचार करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्या मीडिया विचार करेगा?

हम भी जानते हैं कि आपातकाल की स्याह रातों को समाप्त करने में मीडिया की प्रमुख भूमिका रही है। कलम पर कर्फ्यू नहीं लगना चाहिए और न धारा 144, पर इसका यह अर्थ तो नहीं कि मीडिया अनियंत्रित हो जाए। अपने मन की और अपने अर्थों की बात किसी दूसरे के माध्यम से निकाली जाए। अर्थ का अनर्थ करने का अधिकार मीडिया को नहीं है। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण सामने आए, जिसमें मीडिया को नीचे देखना पड़ा। हम सीख नहीं देना चाहते और न हम सिखाना चाहते हैं। पर दायित्व और कर्तव्य का स्मरण कराते रहना हमारा सामाजिक दायित्व है। चैनलों की सनसनी के लिए समाज, संस्था, परिवार और राष्ट्र की संवेदनाओं से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मीडिया को भी संवेदनशील होना ही होगा। जहां मनुष्य होते हैं वहां संवेदनाएं होती हैं। मीडिया भी मनुष्यों का समुच्चय है इसलिए संवेदनाओं से कटे और परे नहीं हो सकते। हमें विश्वास है कि हर घटनाएं सीख देती हैं। 'नरेन्द्र कुमार' के साथ जो घटना घटी और उस पर मीडिया का जो रुख रहा, वह चिंतनीय और शोचनीय है। ■

पेट्रोल मूल्य वृद्धि के विरोध में राजग का 'भारत बंद' पूर्णतः सफल

&dey lans'k C;wjks

31 मई 2012 को जनजीवन ठहर सा गया।

इस दिन भाजपानीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा 'भारत बंद' का आह्वान किया गया था। कारण था– कांग्रेसनीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन द्वारा पेट्रोल की कीमत में साढ़े सात रुपये की अभूतपूर्व वृद्धि।

बंद के दौरान केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारे लगाए गए। नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। जुलुस निकाला गया। संप्रग सरकार का पुतला फूंका गया। वरिष्ठ पार्टी नेताओं सहित लाखों कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दीं। साइकिल, बैलगाड़ी और टमटम की सवारी कर विरोध जताया। 'भारत बंद' का देशव्यापी असर रहा। सड़कें वीरान रहीं। यातायात अवरुद्ध रहे। सड़कों पर वाहन कम दिखे। रेल परिचालन प्रभावित रहा। पेट्रोल पंपों पर ताले लगे रहे। बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। दुकानें एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। पेट्रोल मूल्य वृद्धि से आक्रोशित जनता का बंद में स्वस्फूर्त सहयोग उल्लेखनीय रहा।

विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार यदि महंगाई व पेट्रोल के दाम को नियंत्रित नहीं करती है तो जनता सरकार को 'रोल बैक' कर देगी।

बंद के दौरान राजग के सहयोगी दलों जद–यू ने बिहार, अकाली दल ने पंजाब और शिवसेना ने महाराष्ट्र में पेट्रोल मूल्यवृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

इस राष्ट्रव्यापी बंद का समाजवादी पार्टी और वामपंथ दलों ने समर्थन किया। समाजसेवी श्री अन्ना हजारे ने भी राजग के बंद का समर्थन किया। रिपोर्ट लिखने तक प्राप्त जानकारी के आधार पर हम यहां 'भारत बंद' को लेकर संक्षिप्त विवरण प्रकाशित कर रहे हैं:–

दिल्ली

दिल्ली में बंद का काफी असर देखने को मिला। कनॉट प्लेस, खान मार्केट, साउथ एक्सटेंशन, ग्रेटर कैलाश सहित राजधानी के सभी प्रमुख बाजार बंद रहे। उत्तम नगर टर्मिनल, विकास मार्ग व बदरपुर में प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दिया। मुंडका रेलवे फाटक पर ट्रेन रोककर लोगों ने महंगाई का विरोध जताया। भाजपा के आह्वान पर कनॉट प्लेस, खान मार्केट, साउथ एक्सटेंशन, ग्रेटर कैलाश, चितरंजन पार्क, ग्रीन पार्क, हौजखास बाजार, मालवीय नगर, साकेत, द्वारका, पालम, नजफगढ़, नांगलोई, पश्चिम विहार, मादीपुर, पंजाबी बाग, मोती नगर, राजौरी गार्डन, जनकपुरी, जेल रोड, तिलक नगर, सदर बाजार, पहाड़गंज, चांदनी

चौक, करोलबाग, जामा मस्जिद, सब्जी मंडी, त्रिनगर जयमाता मार्केट, शक्ति नगर, जीटीबी नगर, कश्मीरी गेट ऑटो पार्ट्स मार्केट, प्रीत विहार, विकास मार्ग, कृष्णा नगर मार्केट, पटेल नगर, राजेंद्र नगर, आनंद पर्वत आदि अन्य इलाकों में बंद के चलते शाम तक अधिकांश दुकानें बंद रहीं। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) सर्वश्री रामलाल, राष्ट्रीय महामंत्री अनंत कुमार एवं विजय गोयल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, दिल्ली प्रदेश भाजपाध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता आदि ने दिल्ली में जगह–जगह बंद में हिस्सा लेकर अपनी गिरफ्तारी दी। तीन सौ से अधिक व्यापारिक संगठनों के शामिल होने के कारण बंद सफल रहा।

बंद का असर नई दिल्ली स्थित आइजीआइ एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला। प्रीपेड टैक्सियां नहीं चलीं। एयरपोर्ट से तकरीबन तीन हजार प्रीपेड टैक्सी का संचालन किया जाता है।

राजस्थान

पेट्रोल की दरों में वृद्धि के विरोध में राजग की ओर से देशव्यापी बंद का राजस्थान में प्रभावी असर रहा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने बंद को पूर्णतः सफल होने का दावा करते हुए कहा कि बंद को व्यापक जनसमर्थन मिलने के कारण राज्य में व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। कारोबारियों और निजी शहर टैक्सी संघों और अन्य संगठनों ने बंद का समर्थन किया। बंद समर्थक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर निकले।

पंजाब

पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के खिलाफ राजग के बंद के आह्वान का पंजाब में व्यापक असर रहा। बंद शांतिपूर्ण व सफल रहा। होशियारपुर, रूपनगर, पठानकोट और गुरदासपुर में जहां बंद पूर्णतः सफल रहा, वहीं जालंधर, कपूरथला, पटियाला, चंडीगढ़ व मोहाली में बंद का अच्छा असर रहा। मालवा के अन्य जिलों में भी बंद काफी प्रभावी रहा। फिरोजपुर, फाजिल्का, मोगा, बठिंडा, संगरूर, बरनाला, मानसा, श्री मुक्तसर साहिब, फरीदकोट आदि जिलों में लगभग पूर्णतः बंद रहा। केन्द्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किए गए। केन्द्र सरकार के पुतले भी जलाए गए। लगभग सभी जिलों में भाजपा और शिअद ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका और अलग–अलग डीसी से मिलकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने अमृतसर के निकट अमृतसर–दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग व होशियारपुर जिले में पंजाब–जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात अवरुद्ध किया। इसके अलावा भटिंडा एवं जालंधर में भी राजमार्ग अवरुद्ध रहे। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल तथा भाजपा विधायक दल के नेता व वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री भगत चूनी लाल ने भारत बंद को कामयाब बनाने के लिए राज्य के लोगों विशेषकर व्यापारियों, दुकानदारों, उद्योगपतियों और अन्य वर्गों के साथ अकाली–भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का राज्य भर में भारत बंद को कामयाब बनाने के लिए धन्यवाद किया।

हरियाणा

हरियाणा में 'भारत बंद' सफल रहा। बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। भाजपा–हजकां कार्यकर्ताओं ने यूपीए सरकार का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ पूरे शहर में प्रदर्शन किया। नेताओं के साथ–साथ आम आदमी ने बंद को सफल बनाने में सहयोग देकर गुस्सा प्रगट किया। शहर के तमाम बाजारों की दुकानें बंद रहीं। सिरसा में भाजपा महिला प्रदेशाध्यक्ष रेणु शर्मा ने रिक्शा चलाकर विरोध जताया। करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, फरीदाबाद, हिसार, बरवाला, उकलाना, हांसी, नारनौंद, अग्रोहा, आदमपुर व सिवानी में बंद कामयाब रहा। चण्डीगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रेल पटरी पर धरना दिया।

बिहार

पेट्रोल की कीमत में अभूतपूर्व वृद्धि के विरोध में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा आहूत भारत बंद के दौरान बिहार में बंद समर्थकों ने कई अनोखे तरीके अपनाकर विरोध दर्ज कराया। पटना में कहीं पर विधायकों ने टमटम की सवारी की तो कहीं बंद समर्थकों ने ऑटोरिक्शा को रस्सी से खींचा। कदमकुआं इलाके में तो लोगों ने स्कूटर जलाकर पेट्रोल

में मूल्य वृद्धि का विरोध किया। पटना के कदमकुआं इलाके में बंद समर्थकों ने पुराने स्कूटर के साथ केंद्र सरकार की शव यात्रा निकाली और स्कूटर को जला दिया। इधर, नोखा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक रामेश्वर प्रसाद ने पटना की सड़कों पर टमटम की सवारी की और बंद का समर्थन करते रहे। बिहार में बंद समर्थकों ने पटना के

अति व्यस्ततम डाक बंगला चौराहे को जाम कर दिया जबकि कुछ समर्थक राजेंद्रनगर टर्मिनल पर पटरियों पर बैठ गए। बंद के दौरान जहानाबाद, खगड़िया, दरभंगा, सहरसा, सीवान, कटिहार में भी भाजपा और जनता दल (यू) के कार्यकर्ताओं ने सड़क व रेल मार्ग अवरुद्ध किया।

जम्मू और कश्मीर

पेट्रोल के दाम में वृद्धि के विरोध में राजग के भारत बंद के आह्वान का जम्मू से लेह तक व्यापक असर रहा। जम्मू, कठुआ, ऊधमपुर और राजौरी में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे और ट्रांसपोर्ट सेवा भी प्रभावित रही। चंद छुटपुट घटनाओं को छोड़कर बंद पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। बंद के दौरान जम्मू में जमकर प्रदर्शन हुए, रैलियां निकाली गई और रेल रोकने का भी प्रयास किया गया।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने तांगे की सवारी कर विरोध जताया। प्रदर्शन में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा भी शामिल हुए। भाजयुमो ने यूपीए सरकार के पुतले फूंके। राष्ट्रवादी शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने रघुनाथ बाजार में रैली निकाली। उधर, श्रीनगर में भी मूल्य वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन हुआ।

भाजपा के कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर के लालचौक के पास नारेबाजी करते हुए जुलूस निकालने के प्रयास किए। पहले

से तैनात पुलिस ने जुलूस को नाकाम बनाते हुए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। मुहम्मद अशरफ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लालचौक से सटे प्रेस एनक्लेव के पास जमा हुए। हाथों में बैनर लिए ये लोग यूपीए सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर पेट्रोल की बढ़ी कीमतों को वापस लेने की मांग कर रहे थे।

महाराष्ट्र

पेट्रोल मूल्य वृद्धि और महंगाई के खिलाफ महाराष्ट्र में भाजपा, रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया और शिवसेना बड़े पैमाने पर विरोध–प्रदर्शन किया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। मुम्बई के कार्यालयों में लोगों के लिए भोजन पहुंचाने वाले डब्बावालों ने 31 मई को अपनी सेवाएं नहीं दीं।

मध्य प्रदेश

पेट्रोल मूल्यवृद्धि के विरोध में भारतीय जनता पार्टी और

अन्य दलों द्वारा बुलाए गए बंद के दौरान पूरा प्रदेश जैसे पूरी तरह से ठप हो गया। यह जगजाहिर हो गया कि लोग पेट्रोल मूल्यवृद्धि से परेशान व आक्रोशित हैं और इस महंगाई से अब मुक्ति चाहते हैं, जिसकी वजह से नब्बे फीसदी व्यापारियों ने स्वेच्छा से बंद में अपना सहयोग दिया।

छत्तीसगढ़

पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में बंद का छत्तीसगढ़ में व्यापक असर देखने को मिला। बंद के समर्थन में राजधानी रायपुर और राज्य के सभी प्रमुख शहरों बिलासपुर, रायगढ़, राजनांदगांव और जगदलपुर में बाजार, सिनेमा घर, स्कूल–कॉलेज और पेट्रोल पंप नहीं खुले। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुबह से रायपुर समेत सभी शहरों में पैदल मार्च किया। बस और ऑटो रिक्शा भी नहीं चले। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी पर रैली निकाली। राज्य में चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा बंद को समर्थन के कारण सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे।

उत्तर प्रदेश

पेट्रोल के दाम में वृद्धि को लेकर आयोजित भारत बंद का लखनऊ में व्यापक असर देखने को मिला। हजरतगंज, अमीनाबाद, निशातगंज, चौक, महानगर और डालीगंज में बंद का व्यापक असर देखने को मिला। शापिंग माल भी बंद रहे। वहीं नजीराबाद, नाका हिंडोला और ठाकुरगंज में बंदी का मिलाजुला असर रहा। केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन 31 मई को सुबह से शुरू हो गया जो शाम तक जारी रहा। व्यापारिक संगठनों तथा भारतीय जनता पार्टी व समाजवादी पार्टी की विभिन्न इकाइयों द्वारा हजरतगंज चौराहे

पर प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के पुतले फूंके गए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यालय से प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत बाजपेयी के नेतृत्व में जुलूस निकाला। बैलगाड़ी पर सवार होकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता विधान भवन के समक्ष पेट्रोल मूल्य वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कलराज

मिश्र, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही, सतीश महाना, ज्योत्सना श्रीवास्तव, पूर्व एमएलसी सुभाष त्रिपाठी आदि उपस्थित थे। महंगाई व पेट्रोल के दामों में वृद्धि के खिलाफ व्यापारिक संगठन भी सड़क पर उतरे।

उत्तराखंड

'भारत बंद' को लेकर देहरादून बंद के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह–जगह पर विरोध प्रदर्शन किया। पेट्रोल की कीमत में हुई बेतहाशा वृद्धि का भाजपा विधायकों ने अनूठे अंदाज में विरोध किया। वे पार्टी के प्रदेश मुख्यालय से साइकिल पर सवार होकर विस सत्र में भाग लेने पहुंचे। भाजपा विधायक बंशीधर भगत, बिशन सिंह चुफाल, अरविंद पांडे व सहदेव सिंह पुंडीर सुबह बलवीर रोड स्थित पार्टी मुख्यालय पर एकत्र हुए और वहां से साइकिल पर विधानसभा के लिए निकले।

विधायकों का यह अनूठा अंदाज देखकर लोगों के बीच कौतुहल की स्थिति रही। भाजपा विधायक गणेश जोशी भी पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए साइकिल से घंटाघर पहुंचे। बैलगाड़ी के जरिये विरोध भाजपा कार्यकर्ता मेहूंवाला से आइएसबीटी चौक तक बैलगाड़ियों में पहुंचे। यहां बैलगाड़ी खड़ी कर कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। इससे वहां कुछ देर जाम की स्थिति भी रही। गलियां बनी मैदान बंद के दौरान विभिन्न बाजार की गलियां खेल का मैदान बन गई। बंद के चलते व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साथ ही बैंक, डाकघर व पेट्रोल पंप भी बंद रहे।

झारखण्ड

राज्य में आम जनजीवन प्रभावित हुआ। राज्य के कुछ इलाकों में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे एवं सड़कों पर बस एवं ऑटो रिक्शा नहीं चले। रांची में भारतीय जनता पार्टी के सैंकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। रांची, कोडरमा, धनबाद एवं गिरीडीह में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया।

हिमाचल प्रदेश

मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में पेट्रोल मूल्य वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बंद के समर्थन में हिमाचल में सुबह से दुकानें व व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। शिमला में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे।

पश्चिम बंगाल

पेट्रोल की मूल्य वृद्धि के खिलाफ राजग द्वारा आहूत देशव्यापी बंद का कोलकाता व पासवर्ती अंचलों में प्रभाव देखा गया। बड़ी–बड़ी दुकानें व अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। वाहनों के परिचालन पर बंद का असर पड़ा। इस दौरान पूरे राज्य में सैंकड़ों बंद समर्थक गिरफ्तार किए गए। आसनसोल, वर्द्धमान, उत्तर 24 परगना व मुर्शिदाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बंद को पूरी तरह सफल बनाया। कोलकाता के विभिन्न भागों में बंद समर्थकों को सड़कों पर देखा गया।

ट्रेन सेवा कुछ जगहों पर बाधित हुई। हावड़ा, सियालदह

व खड़गपुर मंडल में रेल परिचालन पर प्रभावित रहा। कोन्ननगर, बारुईपाड़ा, हिंदमोटर, उत्तरपाड़ा स्टेशन पर बंद समर्थक पटरियों पर लेट गए। नई दिल्ली–हावड़ा डाउन राजधानी व नई दिल्ली–सियालदह डाउन राजधानी एक्सप्रेस घंटों विलंब से हावड़ा व सियालदह स्टेशन पहुंची।

कर्नाटक

प्रदेश में राज्य संचालित व निजी बसें सड़कों से गायब

रहीं, दुकानें व होटल बंद रहे और शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश रहे। यातायात बाधित रहा।

तमिलनाडु

राज्या में बंद का असर दिखा। बंद के दौरान कन्याकुमारी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और यूपीए सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। कोयम्बटूर में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे।

ओडिशा

राज्य में भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। भाजपा, सत्तारूढ़ बीजू जनता दल सहित कई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता बंद को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतरे। ■

सफल 'भारत बंद' के लिए देश की जनता को धन्यवाद

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने जनता को स्वतःस्फूर्त और बड़े पैमाने पर भारत बंद को सफल बनाने तथा पेट्रोल की बढ़ी कीमतें वापिस लेने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए धन्यवाद दिया।

भारी गर्मी के बावजूद समाज के सभी वर्गों की भारत बंद में भागीदारी और एनडीए तथा गैर कांग्रेसी दलों की हिस्सेदारी ने बंद को 'विरोध के गठबंधन' का रूप दे दिया।

जनता ने एक स्वर से पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि को वापिस लेने की मांग करके कांग्रेस को यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि यदि कीमत वृद्धि वापिस नहीं ली गई तो जनता आपको सत्ता से अलग कर देगी।

श्री गडकरी ने भारत बंद को शानदार रूप से सफल बनाने के लिए पार्टी के नेताओं और देशभर के कार्यकर्ताओं के अनथक प्रयासों की सराहना की।

भाजपा अध्यक्ष ने एनडीए के सभी घटक दलों और अन्य गैर–कांग्रेसी दलों का विरोध के गठबंधन की शक्ति का सुदृढ़ प्रदर्शन करने के लिये धन्यवाद दिया और कहा कि हम सबके सामूहिक प्रयास से यूपीए की निकम्मी और भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने में इससे मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस की जन–विरोधी नीतियों का विरोध करते रहेंगे और निकम्मी सरकार की सभी क्षेत्रों में असफलता को बेनकाब करते रहेंगे।■

महंगाई के खिलाफ भाजपा का जनसंघर्ष अभियान

7 से 22 जून तक

Hkk रतीय जनता पार्टी द्वारा 7 जून से 22 जून 2012 तक जन संघर्ष अभियान एंव 22 जून को जेल भरो आन्दोलन करने का निर्णय 31 मई 2012 को राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में श्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में लिया गया।

पार्टी अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी ने देश की जनता का 31 मई के बंद में अभूतपूर्व सहयोग के लिये धन्यवाद दिया यह उल्लेखनीय है कि इस बंद को जनता के सभी वर्गों का व्यापक सहयोग मिला।

यूपीए सरकार की गलत नीतियों व महंगाई के विरोध में भाजपा 7 जून से 22 जून 2012 तक देश व्यापी जन संघर्ष अभियान चलायेगी । संघर्ष अभियान कार्यक्रम में तीन मुख्य मुददों पर संघर्ष किया जायेगा।

1. पेट्रोल में किये गये रुपये 7 की वृद्धि को वापस लिया जाये भारत की जनता ने रु 1.60 की कमी के पीछे दुर्भावना को पहचान लिया है तथा वह इससे संतुष्ट नहीं है।
2. गत सात वर्ष के यूपीए सरकार के कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था बद से बदतर हो गयी है । दामों में असीमित बढ़ोतरी के कारण आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। आम आदमी मुद्रास्फीति का असर निर्वाह करने में असमर्थ है यूपीए सरकार इन दामों को कम करने व मुद्रास्फीति की दर को कम करने के लिये उचित कदम उठायें। साथ ही साथ आवश्यक वस्तु के दामों में कमी के लिये काला बाजारी के विरुद्ध सख्त कदम उठायें व आम आदमी विरोधी आर्थिक योजनाओं को समाप्त करें।
3. गत सात वर्षों में गलत शासन नीति देश का दुर्भाग्य है देश के राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार नहीं है वहां यूपीए सरकार का सौतेला व्यवहार रहा है। जिसके कारण वहां की सरकार अपने राज्य में ग्रामीण इलाकों में अच्छा काम व अच्छी सिचांई प्रबन्ध व गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को सहारा देने में असमर्थ हो रही है।

भारतीय जनता पार्टी यह मांग करती है कि यह सौतेला रवैया समाप्त किया जाये वह राज्यों को उचित विकास के संसाधन उपलब्ध कराये जाये। जन संघर्ष अभियान के अन्तर्गत भारतीय जनता पार्टी राज्य व जिला स्तर पर विभिन्न बैठकों का आयोजन करेगा जिसमें राज्य व केन्द्र के नेतागण भाग लेंगे । इस जन संघर्ष अभियान के अन्तिम दिन 22 जून 2012 को पार्टी ने बड़े स्तर पर धरना व, जुलुस का आहवान किया है जो कि जेल भरो आन्दोलन में तब्दील हो जायेगा। ■

प्रदेश सदस्यता प्रभारियों की नियुक्ति

सत्र 2012–2014 के लिए अखिल भारतीय सदस्यता प्रभारी श्री राधामोहन सिंह, सांसद ने निम्नलिखित प्रदेशों के लिए प्रदेश सदस्यता प्रभारियों की नियुक्ति की है। उनके नाम हैं :

çns'k	lnL;rk iez[k
बिहार	श्री संजीव चौरसिया
महाराष्ट्र	श्री चैनसुख संचेती
पंजाब	श्री जीवन गुप्ता
पश्चिम बंगाल	श्री प्रभाकर तिवारी
मणिपुर	यांगलेट हाउकिप
छत्तीसगढ़	श्री गौरीशंकर अग्रवाल

नदियों को परस्पर जोड़ने पर सर्वोच्च न्यायालय का उत्कृष्ट निर्णय

जून 2011 के अंतिम दिनों में मैंने तीन मुद्दों–भ्रष्टाचार, मंहगाई और कालेधन–को मुखरित करने के उद्देश्य से 40 दिन की रथयात्रा की थी।

इस यात्रा के दौरान राजस्थान में शेखावटी के रेगिस्तान क्षेत्र से गुजरते हुए, मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि जब एनडीए की सरकार थी तब प्रधानमंत्री वाजपेयी ने नदियों को जोड़ने के बारे में बोला था तो राजस्थान के किसानों को इससे बड़ा जोश भर गया।

वास्तव में, जब–जब मैं अपने भाषण में एनडीए की इस परियोजना, जिसके सम्बंध में शिव सेना के नेता सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित की गई थी, का उल्लेख करता था तब उपस्थित जनसमूह से अच्छा–खासा भीड़ से समर्थन मिलता था।

सन् 2002 में सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका कर गंगा, कावेरी, वगई और तामबरावनी जैसी नदियों को जोड़कर जल संरक्षण तथा उपलब्ध स्त्रोतों के समुचित उपयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस.एच. कापडिया की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने 27 फरवरी, 2012 को अपने 63 पृष्ठीय फैसले में केन्द्र और राज्य सरकारों को परमादेश (Mandamus) देते हुए निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

64. अपनी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, अन्ततः हम इस जनहित याचिका का निपटान निम्न निर्देशों के साथ करते हैं:

(I) हम भारत की केन्द्र सरकार, विशेष रूप से भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय को निर्देश देते हैं कि वह तुरंत 'नदियों को परस्पर जोड़ने हेतु विशेष समिति' (स्पेशल कमेटी फॉर दि इंटर–लिंकिंग ऑफ रिवर्स') (आगे इसे 'कमेटी'के नाम से पुकारा जाएगा) एक कमेटी गठित करे जिसमें निम्नलिखित सदस्य हों:

1. माननीय मंत्री, जल संसाधन मंत्रालय
2. सचिव, जल संसाधन मंत्रालय,
3. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,
4. चेयरमैन, केंद्रीय जल आयोग,
5. सदस्य–सचिव, राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण,
6. निम्न मंत्रालयों/निकायों से चार विशेषज्ञों को मनोनीत किया जाए:

(क) एक विशेषज्ञ जल संसाधन मंत्रालय से,
(ख) एक विशेषज्ञ वित्त मंत्रालय से,
(ग) एक विशेषज्ञ योजना आयोग से,
(घ) एक विशेषज्ञ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से।

7. प्रत्येक सम्बन्धित राज्यों के जल और/या सिंचाई मंत्री के साथ–साथ उसी राज्य के सम्बन्धित विभाग के प्रधान सचिव।
8. जल सम्बन्धी नदियों को जोड़ने वाली योजना से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े अन्य राज्य के मुख्य सचिव अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो प्रधान सचिव से कम दर्जे का न हो और सम्बन्धित विभाग से हो।
9. सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा मनोनीत दो सामाजिक कार्यकर्ता।
10. श्री रंजीत कुमार, 'न्यायमित्र' (Amicus Curiae)

(II) कमेटी कम से कम दो महीने में एक बार मिलेगी और इसके विचार–विमर्श तथा मिनट्स का रिकार्ड रखेगी।

(III) किसी भी व्यक्ति की अनुपस्थिति के चलते, चाहे उसकी हैसियत कुछ भी हो, बैठक स्थगित नहीं की जाएगी। यदि जल संसाधन के माननीय मंत्री उपलब्ध नहीं हैं, तो जल संसाधन मंत्रालय के सचिव बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

(IV) नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यदि कमेटी को आवश्यक लगे तो वह एक उप–समिति भी

गठित कर सकती है, जिसकी अवधि और शर्तें उपयुक्त हों।

(V) कमेटी, भारत सरकार की केबिनेट को वर्ष में दो बार रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसमें वर्तमान स्थिति (स्टेट्स) प्रगति रिपोर्ट के साथ–साथ अपेक्षित निर्णय भी लिए जाएंगे जिन मामलों को पहले ही बता दिया गया है। केबिनेट देश के हित में शीघ्रतातिशीघ्र सभी अंतिम और उपयुक्त निर्णय लेगी और अच्छा होगा कि उसके सम्मुख रखे गए मामलों के तीस दिन के भीतर यह निर्णय लिए जाएं।

(VI) विशेषज्ञ समितियों सहित सभी रिपोर्टें और इस याचिका के न्यायालय में विचाराधीन अवधि में सौंपी गई सभी स्थिति रिपोर्टों को कमेटी के सम्मुख विचारार्थ हेतु रखा जाएगा। रिपोर्टों और विशेषज्ञ अभिमतों के अपेक्षित विश्लेषण पर कमेटी इस योजना के कार्यान्वयन हेतु इसकी योजनाएं तैयार करेगी।

(VII) योजना इस प्रकार तैयार की जाएगी की उसमें योजना के क्रियान्वयन और पूर्ण करने, योजना, क्रियान्वयन, निर्माण, लागू करने से जुड़े विभिन्न चरण होंगे।

(VIII) हमें सूचित किया गया कि 'केन–बेतवा–योजना' की प्रारम्भिक और विस्तृत रिपोर्टों को तैयार करने पर काफी धन व्यय किया गया है। डीपीआर अब तैयार है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तथा केन्द्र सरकार ने भी पहले ही अपनी स्वीकृति और सहमति दे दी है। मांगे गए स्पष्टीकरणों पर कमेटी द्वारा विचार किया जाएगा। हमे कमेटी को निर्देशित करना चाहेंगे कि वह पहले चरण में इस परियोजना को क्रियान्वयन के लिए हाथ में ले।

(IX) विशेषज्ञ रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए, हमें यह मानने और निर्देश देने में कोई संकोच नहीं है कि नदियों को जोड़ने वाली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में समय एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कारक है। जैसाकि एनसीएइआर तथा स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि विलम्ब से सम्बन्धित पक्षों और लोगों को होने वाले वित्तीय लाभ बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और वास्तव में सभी सम्बन्धित पक्षों पर वित्तीय दवाब बनाए हुए हैं।

(X) यह निर्देशित किया जाता है कि कमेटी व्यवहार्यता रिपोर्टों या अन्य रिपोर्टों को पूरा करने के लिए कड़े कदम उठाएगी और एक निश्चित समय सीमा तय करेगी और योजनाओं को पूरा करने को सुनिश्चित करेगी ताकि लाभ सही समय और लागत में मिल सकें।

(XI) प्रारम्भिक चरणों में, इस कार्यक्रम में उन राज्यों को शामिल नहीं किया जाएगा जिनके पास पर्याप्त जल है और नदियों को आपस में जोड़ने के किसी कार्यक्रम से वे ठोस रूप से नहीं जुड़े हैं और योजनाएं उनकी प्रभावी भागीदारी के बिना भी पूरी की जा सकती हैं।

(XII) हालांकि, कमेटी किसी भी राज्य को कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के किसी भी चरण में शामिल कर सकती है।

(XIII) अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिन पर पेपर वर्क पिछले दस वर्षों से ज्यादा समय से और जनता के धन की बड़ी कीमत पर चल रहा है इसलिए, हम केन्द्र और राज्य सरकारों को इस कार्यक्रम में भाग लेने का निर्देश देते हैं और सभी वित्तीय, प्रशासनिक तथा इन योजनाओं को और प्रभावी ढंग से पूरा करने हेतु सहायता उपलब्ध कराने का भी।

(XIV) रिकार्ड से यह साफ दिखता है कि टास्क फोर्स द्वारा सौंपी गई रिपोर्टों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अतः, टास्क फोर्स द्वारा किए गए सारे प्रयास, एक प्रकार से सम्बन्धित सरकारों, और जनता के लिए किसी उपयोग के नहीं रह गए हैं। टास्क फोर्स को समाप्त कर दिया गया है। टास्क फोर्स की रिपोर्टें कमेटी के सम्मुख रखी जाएं जो निस्संदेह, इसमें दिए गए सुझावों पर विचार करते हुए निर्णय करेगी कि कैसे इनको जनता के लाभ हेतु क्रियान्वित किया जाए।

(XV) इस निर्णय के तहत गठित कमेटी नदियों को जोड़ने वाले कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की जिम्मेवार होगी। इसके निर्णय, इस न्यायालय या अन्य के आदेश से गठित सभी प्रशासनिक निकायों के ऊपर लागू होंगे।

(XVI) इस निर्णय में वर्णित निर्देशों के कार्यान्वयन न होने या असफल होने की दशा में हम 'न्याय मित्र' (Amicus Curiae) को अवमानना याचिका दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं।

65) यदि हम विद्वान 'न्याय मित्र' (Amicus Curiae) द्वारा दी गई मूल्यवान और योग्य सहायता

और अन्य सभी वरिष्ठ वकीलों और उनके सहायकों द्वारा वर्तमान पीआईएल के संदर्भ में पेश होने के सम्बन्ध में रिकार्ड में अपनी प्रशंसा नहीं दर्ज कराते तो हम अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाएंगे।

♦♦♦

यदि कोई मुझसे पूछे कि वाजपेयीजी की एनडीए सरकार की मुख्य उपलब्धियां क्या थीं, तो मैं इन तीन को रेखांकित करूंगा:

पहली, इसने पाकिस्तान के साथ शांति और सामान्य सम्बन्ध बनाए रखने में अपनी गंभीरता प्रदर्शित की लेकिन साथ ही वाजपेयी सरकार ने पाकिस्तान के पूर्वाग्रही सैन्य इरादों और सीमापर के आतंकवाद के बारे में, अपने जीरो टॉलरेन्स रवैये को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया। इसलिए सत्ता में आने के दो महीनों के भीतर एनडीए सरकार ने भारत को परमाणु शक्ति बना दिया।

दूसरी, एनडीए सरकार ने समूचे देश के लिए राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क के लिए एक ठोस नींव रखी।

तीसरी, एनडीए सरकार ने मुख्य नदियों को आपस में जोड़ने का न केवल महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तैयार किया अपितु इस काम को विशेष रूप से करने के लिए एक वरिष्ठ मंत्री सुरेश प्रभु को भी काम में जुटाया। हाल ही में सुरेश प्रभु मुझे मिले थे और उन्होंने इस हेतु किए गए दुसाध्य कार्य का विस्तृत व्यौरा मुझे बताया। उन्होंने देश के सभी राज्यों में 5 हजार से ज्यादा छोटी और बड़ी मीटिंग कीं। इसके अलावा उन्होंने आईसीआईसीआई के चेयरमैन के.वी. कामत की अध्यक्षता में वित्तिय विशेषज्ञों और प्रमुख बैंकरों की एक कमेटी गठित की जिसने नदियों को आपस में जोड़ने की इस योजना के लिए एक अत्यन्त नवीन और दूरगामी योजना तैयार की।

सुरेश प्रभु ने मुझे बताया कि विशेषज्ञों का यह समूह पूरी तरह आश्वस्त था कि वे नदियों को जोड़ने की योजना के लिए कम से कम 5,60,000 करोड़ रूपये का निवेश जुटाने में सफल होंगे।

एक और तथ्य सुरेश प्रभु ने बताया कि प्रभावी योजना आयोजन और निगरानी हेतु डा0 कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 'इसरो' (ISRO) रिमोट सेंसिंग, जीआईओएस, सेटेलाइट इमेजनरी का उपयोग करने हेतु सहमत हो गए थे।

♦♦♦

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए इस फैसले को तीन महीने बीत चुके हैं। और न्यायालय जिस स्पेशल कमेटी का गठन चाहता था, वह अभी तक नहीं हुआ है। किसी को आश्चर्य नहीं होगा यदि 'न्याय मित्र'(Amicus Curiae) श्री रंजीत कुमार, जिनको इस केस में अपना योगदान देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनंदित किया है, न्यायालय की विशेष सलाह को मानते हुए जल संसाधन मंत्रालय के 'दोष' के विरूद्ध अवमानना याचिका दायर करें तो! ■

शिमला (हि.प्र.) नगर निगम चुनाव

कांग्रेस की ऐतिहासिक पराजय और भाजपा के लिए विजय संकेत

मई 2012 चुनावों में कांग्रेस बुरी तरह से पराजित हुई जिसमें उसने शिमला म्युनिसिपिल कार्पोरेशन में उसकी बुरी तरह हार हुई जहां पर वह 1987 से अधिकार जमाए बैठी थी। हिमाचल हाई कोर्ट के आदेशों पर पहली बार म्युनिसिपिल निकाय के सीधे चुनाव कराए गए थे। महापौर और उप–महापौर के चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह हारना पड़ा, जबकि उसके उम्मीदवार पिछड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गए थे। उधर भाजपा ने 12 सीटें जीतकर अपनी सदस्य संख्या बढ़ा कर 50 प्रतिशत सीटों पर विजयी रही, जो पूरे बहुमत से मात्र एक सीट पीछे थी, जबकि उसने पिछली बार 8 सीटों पर विजय प्राप्त की थी; कांग्रेस को मात्र 10 सीटों से संतोष करना पड़ा जबकि पिछली बार उसके पास 16 सीटें थी। सीपीएम (मार्क्सवादी) को तीन सीटें मिलीं जिससे उसकी संख्या में 1 सीट की बढ़ोतरी हुई। महापौर और उप–महापौर पदों के लिए पहली बार सीधा चुनाव हुआ, जिसमें सीपीआई (एम) ने दोनों पदों पर विजय प्राप्त की। महापौर पद के लिए सीपीआई (एम) को 42.55 प्रतिशत वोट मिले, भाजपा को 27.46 तथा कांग्रेस को 25.98 प्रतिशत वोट मिले। उप–महापौर के लिए सीपीआई (एम) को 40.91 प्रतिशत, भाजपा को 31.69 प्रतिशत तथा कांग्रेस को 25.49 वोट प्राप्त हुए।

अब हिमाचल प्रदेश विधान सभा चुनावों के लिए मात्र छह महीने से कम की अवधि रह गई तो इस स्तब्धकारी पराजय से कांग्रेस का मनोबल बुरी तरह से गिरा है और नेता एक दूसरे पर इस हार के लिए आरोप लगाने में जुट गए हैं। कांग्रेस की नीचे गिरती जा रही प्रतिष्ठा से भाजपा के लिए यह एक अच्छा शगुन है। पार्टी कार्यकर्ताओं में इससे बहुत भारी विश्वास और उत्साह का संचार हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने बहुत स्पष्ट कहा है कि ''निश्चित ही लोगों ने कांग्रेस को खारिज कर दिया है।'' ■

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस (23 जून) पर विशेष

अखण्ड भारत के पुरोधा

& Mk- egs'k pUæ 'kekZ

Mk- श्यामा प्रसाद मुखर्जी मूलतः शिक्षा से जुड़े हुए विद्वान व्यक्ति थे। शिक्षाविद एवं विधिवेत्ता होने की योग्यता उन्हें विरासत में प्राप्त हुयी थी। वे संवेदनशील समाजकर्मी, राष्ट्रवादी राजनेता एवं प्रखर सांसद बने। उन्होंने युगधर्म के आह्वान को स्वीकार किया।

राष्ट्रीय एकात्मता एवं अखण्डता के प्रति उनकी आगाध श्रद्धा ने उन्हें राजनीति के समर में झोंक दिया। अंग्रेजों की 'फूट डालो व राज करो' की नीति ने मुस्लिम लीग को स्थापित किया था। डॉ. मुखर्जी ने हिन्दू महासभा का नेतृत्व ग्रहण कर इस नीति को ललकारा। महात्मा गांधी ने उनके हिन्दू महासभा में शामिल होने का स्वागत किया क्योंकि उनका मत था कि हिन्दू महासभा में मालवीय जी के बाद किसी योग्य व्यक्ति के मार्गदर्शन की जरूरत थी। कांग्रेस यदि उनकी सलाह को मानती तो हिन्दू महासभा कांग्रेस की ताकत बनती तथा मुस्लिम लीग की भारत विभाजन की मनोकामना पूर्ण नहीं होती।

बिना परमिट लिए उन्होंने 'एक देश में दो विधान, एक देश में दो प्रधान, एक देश में दो निशान– नहीं चलेंगे– नहीं चलेंगे' के नारे लगाते हुये जम्मू–कश्मीर में प्रवेश किया। शेख अब्दुल्ला की सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। वहां उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। भारत की अखण्डता के लिए आजाद भारत में, यह पहला बलिदान था।

कांग्रेस ने विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार करते हुये पूरे बंगाल एवं पूरे पंजाब को पाकिस्तान को देना स्वीकार कर लिया था। डॉ. मुखर्जी ने इसका प्रखर विरोध किया, परिणामतः बंगाल एवं पंजाब का विभाजन हुआ। विभाजन के संदर्भ में पंडित नेहरू के एक आरोप के जवाब में मुखर्जी ने कहा 'आपने भारत का विभाजन करवाया तथा मैंने पाकिस्तान का विभाजन करवाया है।'

डॉ. मुखर्जी मुस्लिम विरोधी नहीं वरन् मुस्लिम लीग विरोधी थे। 1937 के चुनावों में डॉ. मुखर्जी के प्रयत्नों ने बंगाल में मुस्लिम लीग को धूल चटाई तथा ए.के. फजलुल हक की अध्यक्षता वाली कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बंगाल में बनी। डॉ. मुखर्जी स्वयं इस सरकार में शामिल हुए। दुर्भाग्य से 1946 के चुनावों में सिंध व बंगाल में मुस्लिम लीग सरकार बनाने में सफल हो गयी। मुस्लिम लीग कलकत्ता और लाहौर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए कटिबद्ध थी। डॉ. मुखर्जी के प्रयत्नों से कलकत्ता तो बच गया, लेकिन लाहौर को बचाना सम्भव नहीं हुआ। डॉ. मुखर्जी ने कांग्रेस में जाने की बजाय हिन्दू महासभा में काम करना तय किया था। लेकिन कलकत्ता में उन्होंने हिन्दू महासभा छोड़ दी, क्योंकि महासभा ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया कि महासभा सभी भारतीयों के लिए अपनी सदस्यता के द्वार खोल दे। महात्मा गांधी के आग्रह पर कांग्रेसी न होते हुए भी डॉ. मुखर्जी पंडित जवाहर लाल नेहरू के प्रथम मंत्रिमण्डल में शामिल हुये। वे भारत के प्रथम उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री बने। भारत की औद्योगिक नीति की नींव उनके ही द्वारा डाली गयी। लेकिन नेहरू की पाकिस्तान पोषक एवं हिंदू उपेक्षा की नीति के साथ चलना उनके लिए सम्भव नहीं था। अतः 8 अप्रैल, 1950 को अढ़ाई साल बाद, उन्होंने मंत्रिमण्डल से त्यागपत्र दे दिया। सत्ता उनके व्यक्तित्व को बांधने में विफल रही, उन्होंने अपनी शर्तों पर राजनीति की।

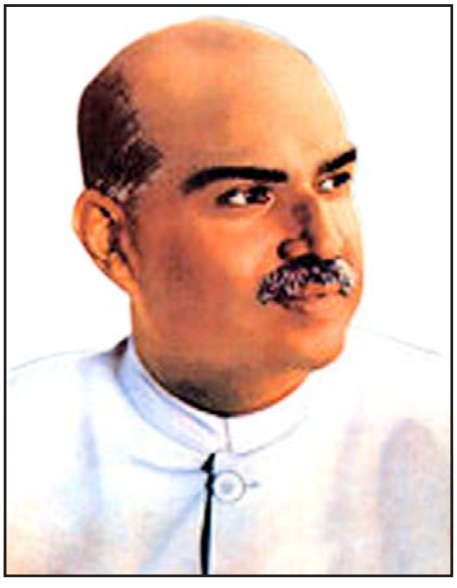

मंत्रिमण्डल से बाहर आकर उन्होंने राष्ट्रवादी राजनैतिक दल के अपने संकल्प को पूरा किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक श्री माधवराज सदाशिवराव गोलवलकर (गुरुजी) की सहायता से भारतीय जनसंघ की स्थापना की। आजादी के आंदोलन

में भारत की अखण्डता की रक्षा का मिशन लेकर डॉ. मुखर्जी राजनीति में आये थे। जनसंघ की स्थापना के साथ ही कश्मीर को भारत का अविभाज्य हिस्सा बनाने का आंदोलन उन्होंने प्रारम्भ किया। कश्मीर को विशेष सम्प्रभुता देकर धारा 370 के अधीन अलग संविधान, अलग कार्यपालिका तथा अलग झंडा देने के प्रस्ताव को, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपनी स्वीकृति दे चुके थे। संसद में बहस, आपसी वार्तालाप एवं पत्राचार के माध्यम से, उन्होंने सरकार को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन अंततः उन्हें इसके विरोध में सत्याग्रह करना पड़ा।

बिना परमिट लिए उन्होंने 'एक देश में दो विधान, एक देश में दो प्रधान, एक देश में दो निशान– नहीं चलेंगे– नहीं चलेंगे' के नारे लगाते हुये जम्मू–कश्मीर में प्रवेश किया। शेख अब्दुल्ला की सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। वहां उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का खुलासा आज तक नहीं हो सका है। भारत की अखण्डता के लिए आजाद भारत में, यह पहला बलिदान था। परिणामतः शेख अब्दुल्ला हटाये गये तथा अलग संविधान, अलग प्रधान एवं अलग झण्डे का प्रावधान निरस्त हुआ। धारा 370 के बावजूद कश्मीर आज भारत का अभिन्न अंग बना हुआ है। इसका श्रेय सबसे अधिक डॉ. मुखर्जी को जाता है।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्र थे। 1924 में वे विश्वविद्यालय की सिंडिकेट व सीनेट में सदस्य चुने गये तथा बंगाल विधान परिषद् में, कलकत्ता विश्वविद्यालय का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। 1936 में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी 33 वर्ष की कम उम्र में, कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बन गये। कुलपति के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने बंगला भाषा में दीक्षान्त भाषण दिया और इसके साथ ही बंगाल और अन्य भारतीय भाषाओं पर अंग्रेजी के प्रभुत्व का युग समाप्त हो गया। भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा में दिया गया यह प्रथम दीक्षान्त भाषण था।

1943 में बंगाल एक कृत्रिम अकाल का शिकार हुआ। डॉ. मुखर्जी ने इस अकाल का पूरी ताकत से सामना किया। उन्होंने अपनी साख दांव पर लगा देश को धन देने का आह्वान किया, लोगों का उचित प्रतिसाद प्राप्त हुआ तथा लाखों लोगों को मौत के कराल जाल से बचा लिया गया। उनका बहुआयामी व्यक्तित्व था। वे महाबोधि संगठन के भी अध्यक्ष बने, वे संविधान सभा में चुने गये, वे सांसद तथा मंत्री भी रहे। अनेक क्षेत्रों में, उनकी अद्भुत संवेदनशीलता, राष्ट्रभक्ति एवं प्रतिभा का प्रकटीकरण हुआ। राष्ट्र को उनकी सबसे महत्वपूर्ण देन थी भारतीय जनसंघ नामक राष्ट्रवादी राजनैतिक दल।

नीति के आधार पर वे स्वयं सत्ता छोड़ आये थे। वे प्रखर नेता थे। संसद में भारतीय जनसंघ छोटा दल था, लेकिन उनके नेतृत्व में संसद में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल गठित हुआ, जिसमें गणतंत्र परिषद, अकाली दल, हिन्दू महासभा एवं अनेक निर्दलीय सांसद शामिल थे। जब संसद में पंडित नेहरू ने भारतीय जनसंघ को कुचलने की बात कही तब डॉ. मुखर्जी ने कहा, ''हम देश की राजनीति से इस कुचलने वाली मनोवृत्ति को कुचल देंगे।'' उनकी शहादत पर शोक व्यक्त करते हुए तत्कालीन लोकसभा के अध्यक्ष श्री जी. वी. मावलंकर ने कहा, ''...वे हमारे महान देशभक्तों में से एक थे और राष्ट्र के लिए उनकी सेवाएं भी उतनी ही महान थीं। जिस स्थिति में उनका निधन हुआ वह स्थिति बड़ी ही दुःखदायी है। यही ईश्वर की इच्छा थी। इसमें कोई क्या कर सकता था? उनकी योग्यता, उनकी निष्पक्षता, अपने कार्यभार को कौशल्यपूर्ण निभाने की दक्षता, उनकी वाक्पटुता और सबसे अधिक उनकी देशभक्ति एवं अपने देशवासियों के प्रति उनके लगाव ने उन्हें हमारे सम्मान का पात्र बना दिया।'' ■

अमरनाथ यात्रा आंदोलन

हिंदू भावनाओं के साथ न खेले जम्मू-कश्मीर सरकार : भाजपा

4 जून 2012, जम्मू। भाजपा सांसद जे.पी. नड्डा (राष्ट्रीय महासचिव, भाजपा) और तरुण विजय (राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा) ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जम्मू में अमरनाथ यात्रा की अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर गिरफ्तारी दी। पहले यह यात्रा 60 दिनों के लिए तय की गयी थी जिसे अब घटाकर मात्र 39 दिनों में ही यात्रा समाप्त करने का कार्यक्रम बनाया गया है, जो तीर्थयात्रियों के लिए क्रोध का कारण बना हुआ है तथा उनकी भावनाओं ठेस पहुचायी जा रही है। इस पर श्री तरुण विजय ने कहा कि जम्मू–कश्मीर सरकार को सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए न कि अलगाववियों को प्रदेश के अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर तानाशाही करने की अनुमति। श्री विजय ने कहा कि तीर्थयात्रियों की मांगे पूरी नहीं हुई तो हम सड़क पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे।■

गुजरात के राज्यपाल को हटाएं

महामहिम राष्ट्रपति को भारतीय जनता पार्टी द्वारा 30 मई, 2012 को दिया गया ज्ञापन

भाजपा ने गुजरात की राज्यपाल श्रीमती कमला बेनीवाल पर एक हजार करोड़ रुपए की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए उन्हें राज्यपाल के पद से हटाने की मांग की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में पार्टी नेताओं के एक प्रतिनिधिमण्डल ने 30 मई को राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल से भेंट की और इस संबंध में उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन का पूरा पाठ हम यहां प्रकाशित कर रहे हैं:–

महामहिम राष्ट्रपति जी,

हम आपका ध्यान कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार, जयपुर, राजस्थान, के दिनांक 02.05.2012 के आदेश की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। उक्त आदेश द्वारा धोखाधड़ी के उपायों से प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा राजस्थान में 1000 करोड़ रूपये की सरकारी जमीन हथियाने का मामला उजागर हुआ है। दुर्भाग्य से उक्त आदेश में जिन व्यक्तियों का नाम लिया गया है उनमें गुजरात की राज्यपाल डॉ. कमला बेनीवाल भी हैं।

हाल ही में समाप्त हुए संसद के बजट सत्र में दोनों सदनों में यह मामला उठाया गया था। मीड़िया ने भी मामलें की गम्भीरता की ओर ध्यान खींचा है। जनता डॉ. कमला बेनीवाल से संतोषजनक जवाब की आशा करती है। लेकिन वह चुप्पी साधे बैठी हैं। राजस्थान सरकार इस घोटाले का गम्भीरता से संज्ञान नहीं ले रही।

जयपुर के कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के कार्यालय ने सोसायटी और उसके सदस्यों के खिलाफ और डॉ. कमला बेनीवाल के खिलाफ जो गम्भीर टिप्पणियां की हैं, उन्हें देखते हुए डॉ. कमला बेनीवाल का गुजरात के गवर्नर पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। संवैधानिक औचित्य का तकाजा है कि उन्हें अविलम्ब अपना पद त्याग देना चाहिए।

डॉ. कमला बेनीवाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा गुजरात के राज्यपाल के पद पर नियुक्त है। अतः भारतीय जनता पार्टी आपसे इस मामले में हस्तक्षेप करने और जब तक पूरे भूमि घोटाले की पूरी तरह जांच न हो जाये तब तक गुजरात की राज्यपाल डॉ. कमला बेनीवाल को अपना पद त्याग करने का निर्देश देने की अपील करती है।

राजस्थान सरकार से भी यह स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए कि उसने सोसायटी और उसके सदस्यों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की? रजिस्ट्रार ने अपने आदेश में कहा है ''पिछले 58 वर्षों से 16 घण्टे के खेती श्रम करने का दावा (सोसायटी के सदस्यों और डॉ. कमला बेनीवाल द्वारा) सरासर झूठ है''।

आदेश से यह स्पष्ट हो जाता है कि गुजरात की वर्तमान राज्यपाल गैर कानूनी तरीके से सोसायटी की कार्यकारिणी की सदस्य बन गयीं और भ्रष्टाचार में लिप्त हो गयीं।

डॉ. कमला बेनीवाल के खिलाफ तत्काल कार्यवाही किये जाने के अपने आग्रह की पुष्टि के लिए हम निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहे हैं :–

1. रजिस्ट्रार का 2 मई 2012 का आदेश।
2. किसान सामूहिक कृषि सहकारी समिति, जयपुर के विभिन्न प्रस्ताव और कार्यवाही का वृत्त।
3. राजस्थान सरकार की तथ्य/स्थिति रिपोर्ट।
4. किसान सामूहिक कृषि सहकारी समिति जयपुर, राजस्थान का 2011 का प्रस्ताव जिसमें उल्लेख है कि डॉ. कमला बेनीवाल सहित सोसायटी के सभी सदस्यों ने 58 वर्ष से 16 घण्टे रोजाना खेती करने का दावा किया है।
5. अन्य दस्तावेज।

हम आशा करते है कि महामहिम हमारी अपील पर अनुकूल विचार करेंगी।

भवदीय
(नितिन गडकरी)
राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

Mk- fdjhV lkse;k
राष्ट्रीय मंत्री, भाजपा

v#.k proZsnh
प्रदेश अध्यक्ष,
राजस्थान भाजपा

cychj iqat
संसद सदस्य

HkwiUæ ;kno
राष्ट्रीय मंत्री, भाजपा

vtqu e?koky
संसद सदस्य

■

'चयन मंडल' करे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति

भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए विशेष चयन मंडल बनाने की मांग की। श्री आडवाणी ने इस चयन मंडल में प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा दोनों सदनों के विपक्ष के नेताओं को शामिल करने का सुझाव दिया है। 2 जून को लिखे इस पत्र का हम हिंदी भावानुवाद यहां प्रकाशित कर रहे हैं:–

प्रिय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी,

मैं आपको यह पत्र एक महत्वपूर्ण विषय पर लिख रहा हूं जो भारत के ऐसे सभी लोगों के मन को आंदोलित कर रहा है जो हमारे चुनावी और शासन–व्यवस्था में प्रगतिदायक सुधार देखने के इच्छुक हैं।

इसी माह बाद में मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री एस.वाई. कुरैशी के सेवा–निवृत्ति के कारण निर्वाचन आयोग में एक रिक्त स्थान बन जाएगा। यह रिक्त स्थान किस प्रकार भरा जाए, जो एक ऐसा विषय है जिसमें लोगों की दिलचस्पी और चिंता दोनों ही बराबर मात्रा में बने हुए हैं। देश में इस प्रकार की राय तेजी से बढ़ रही है, जो मानते हैं कि निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं में नियुक्तियों का आधार द्विपक्षीय पद्धति पर होना चाहिए ताकि ऐसे किसी भी भाव से बचा जा सके जो पूर्वाग्रह की छाप छोड़ता हो अथवा पारदर्शिता एवं निष्पक्षता की कमी को दर्शाता हो। भारत के लोगों की गहन इच्छा है कि इस प्रकार की अति महत्वपूर्ण संस्थाओं में केवल अत्यंत सक्षम, ईमानदार और दोषमुक्त सेवा रिकार्ड रखने वाले लोगों को ही नियुक्त किया जाए क्योंकि उनके कामकाज से हमारी शासन–पद्धति की गुणवत्ता बहुत हद तक निर्धारित होती है।

वर्तमान पद्धति में, निर्वाचन आयोग के सदस्यों को एकमात्र प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है जिससे लोगों में उतना विश्वास नहीं बना रहता है। इस प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णयों को सत्ताधारी पार्टी पर छोड़ दिए जाने से चयन प्रक्रिया कमजोर पड़ जाती है जो जोड़–तोड़ और पक्षपातपूर्ण जैसे भावों को जन्म देती है। दरअसल इस पद्धति की विश्वसनीयता पर उस समय गहरा आघात लगा था जब कुछ वर्ष पूर्व ही सीईसी के महत्वपूर्ण पद पर एक संदिग्ध व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया था। अतः समय आ गया है कि निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं सीवीसी और सीआईसी के मामले में किया गया है। सीवीसी और सीआईसी के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण इस प्रकार का परिवर्तन आया है। बेहतर होगा कि सरकार स्वयं ही इस बार पहल कर के पूर्ण बदलाव लाए।

मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि आपकी अपनी सरकार द्वारा नियुक्त द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) ने 2009 की अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि निर्वाचन आयोग के सीईसी एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति 'चयन मंडल' द्वारा की जाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में यह सिफारिश 'एथिक्स इन गवर्नेंस' अर्थात् शासनपद्धति के नीति–शास्त्र में प्रकाशित की गई थी।

इस प्रसंग में, मैं आपसे बड़े दृढ़ संकल्प से अनुरोध करना चाहूंगा कि निर्वाचन आयोग के नए सदस्यों की नियुक्ति एक व्यापक आधार पर बनाए गए 'कालेजियम' द्वारा की जाए जिसमें निम्नलिखित शामिल हों:

1.	प्रधानमंत्री,	अध्यक्ष
2.	भारत कें प्रधान न्यायाधीश,	सदस्य
3.	विधि तथा न्याय मंत्री,	सदस्य
4.	प्रतिपक्ष का नेता (लोकसभा),	सदस्य
5.	प्रतिपक्ष का नेता (राज्यसभा),	सदस्य

शेष पृष्ठ 20 पर

राजनीतिक ईमानदारी पर सवाल

& cychj i|t

fo गत 3 जून को दिल्ली स्थित संसद मार्ग पर एक बार फिर देश के विभिन्न प्रांतों के लोग योग गुरु स्वामी रामदेव और गांधीवादी नेता अन्ना हजारे के नेतृत्व में एकत्रित हुए। उन्होंने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए सशक्त जनलोकपाल कानून बनाने और विदेशों में जमा काले धन की वापसी की मांग दोहराई। कमरतोड़ महंगाई से त्रस्त आम आदमी सरकार के अड़ियल रवैये से आजिज आ चुका है और अब वह निर्णायक लड़ाई छेड़ने के मूड में है। लोगों को प्रधानमंत्री की ईमानदारी पर भले संदेह नहीं हो, किंतु कोयला घोटाले के बाद स्वाभाविक तौर पर जनता की अपेक्षा यह है कि अब उन्हें राजनीतिक ईमानदारी दिखानी चाहिए और भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जन अपेक्षाओं के विपरीत प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा कोयला घोटाले में आरोप साबित होने पर संन्यास लेने की घोषणा हास्यास्पद नहीं तो और क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा कोयला घोटाले की जांच जहां एक ओर सीबीआई को सौंप दी गई है वहीं सीबीआई की मानें तो उसके एजेंडे में किसी राजनीतिज्ञ से पूछताछ करना शामिल नहीं है। तो फिर जांच किस बात की होगी?

सन 2006 से 2009 के बीच पहले आओ, पहले पाओ की नीति पर निजी कंपनियों और सार्वजनिक उपक्रमों को सस्ती दरों पर आवंटित किए गए कोल ब्लॉक्स बाद में अन्य कंपनियों को ऊंची दरों पर बेच दिए गए। 17,000 करोड़ मीट्रिक टन कोयला औने–पौने दामों में निजी कंपनियों को बेचने के मामले में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका संदिग्ध है। जिन 156 कंपनियों का नाम इस घोटाले में शामिल है उनमें से कुछ नामी कंपनियों ने कोल ब्लॉक का संचालन अन्य कंपनियों को सौंप खुद मोटा मुनाफा कमाया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अनुसार कोयले की नीलामी नहीं किए जाने से सरकार को एक लाख अस्सी हजार करोड़ रुपये की चपत लगी है। उपरोक्त कोयला आवंटन की अवधि में कोयला मंत्रालय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अधीन ही था। यह सभी जानते हैं कि सीबीआइ प्रधानमंत्री के अधीन है। सवाल उठता है कि सीबीआइ फिर प्रधानमंत्री से कैसे पूछताछ करेगी और यदि नहीं कर पाएगी तो इस जांच का मतलब क्या है? पहले आओ, पहले पाओ की नीति का अनुसरण करने के कारण 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में भी राजकोष को करीब एक लाख 76 हजार करोड़ रुपये का चूना लगा था। क्या यह महज संयोग है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय की सामूहिक जवाबदेही मंत्रिमंडल की होती है। मंत्रिमंडल का मुखिया होने के नाते मंत्रिमंडल स्तर पर मचाए जा रहे लाखों करोड़ की लूट से आखिर प्रधानमंत्री अपना पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं?

संप्रग–2 कार्यकाल में घोटालों का जिस तरह पहाड़ खड़ा हुआ है उससे यह अब स्थापित हो चुका है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे मंत्रिमंडल के मुखिया हैं और वह सारा तमाशा देख रहे हैं। उनकी इस लाचारी की वजह क्या है? एक सफल अर्थशास्त्री होने के बावजूद वह निष्क्रिय साबित क्यों हो रहे हैं? संप्रग की पहली पारी में वह कम्युनिस्टों के दबाव में थे, किंतु दूसरी पारी में, खासकर 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले से द्रमुक पार्टी के नरम पड़ जाने के बाद सरकार सन्निपात की शिकार क्यों है? इस लकवाग्रस्त सरकार में व्याप्त नेतृत्वहीनता और निर्णयहीनता का खामियाजा आज किसे भोगना पड़ रहा है? आइपीएल, राष्ट्रमंडल खेल, 2जी स्पेक्ट्रम, सेटेलाइट स्पेक्ट्रम, आदर्श सोसायटी घोटाला, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर दागदार व्यक्ति की नियुक्ति और अब कोयला घोटाले में प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री की संलिप्तता

इस लकवाग्रस्त सरकार में व्याप्त नेतृत्वहीनता और निर्णयहीनता का खामियाजा आज किसे भोगना पड़ रहा है? आइपीएल, राष्ट्रमंडल खेल, 2जी स्पेक्ट्रम, सेटेलाइट स्पेक्ट्रम, आदर्श सोसायटी घोटाला, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर दागदार व्यक्ति की नियुक्ति और अब कोयला घोटाले में प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री की संलिप्तता ने भारत की साख को धूल में मिला दिया है।

ने भारत की साख को धूल में मिला दिया है। इन घोटालों से प्रधानमंत्री के साथ–साथ समूची संप्रग सरकार की विश्वसनीयता धुल चुकी है। इससे पूरी दुनिया में भारत को एक भ्रष्ट देश के रूप में देखा जा रहा है, जिसे कल तक एक अत्यंत ऊर्जावान और उदीयमान सशक्त अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया सम्मान के भाव से देख रही थी और देश–विदेश के निवेशक यहां पूंजी निवेश के लिए उत्सुक थे। आज देश की अर्थव्यवस्था एक बार फिर सन 1991 की तंगहाली और कंगाली की स्थिति की ओर अग्रसर है। तब सरकारी खजाने में विदेशी मुद्रा की खासी कमी हो गई थी। हालात इतने बदतर हो गए थे कि भारत को अपनी अंतरराष्ट्रीय देनदारियों की पूर्ति के लिए अपना स्वर्ण भंडार गिरवी रखना पड़ा था।

प्रधानमंत्री पद पर आसीन ख्यातिप्राप्त अर्थशास्त्री और सरकार के आर्थिक सलाहकार चारों खाने चित हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है। रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। रुपये की कीमत में लगातार गिरावट जारी है। पिछले नौ माह में रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले 25 फीसदी तक घट चुकी है। मुद्रास्फीति में कमी करने के लिए रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में लगातार वृद्धि जारी रखी, किंतु महंगाई बेकाबू है। अब रिजर्व बैंक ने भी हाथ खड़े कर सरकार से नीतिगत हस्तक्षेप करने और आर्थिक सुधारों की गति को बढ़ावा देने की अपील की है। रिजर्व बैंक ने बढ़ते व्यापार घाटे पर भी अंकुश लगाने की बात की है, जबकि सच्चाई यह है कि गलत आर्थिक नीतियों के कारण जहां निर्यात में कमी आ रही है वहीं बढ़ते आयात के कारण व्यापार घाटा निरंतर बढ़ता जा रहा है।

सरकारी अकर्मण्यता का अंदाजा हाल ही में जारी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के ताजा आंकड़ों से लगाया जा सकता है। वित्त वर्ष 2011–12 की मार्च में समाप्त चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि पिछले नौ साल के न्यूनतम स्तर पर गिरकर 5.3 प्रतिशत रह गई। इसके साथ ही सालाना जीडीपी वृद्धि भी घटकर 6.5 फीसदी पर आ गई। पहले के मुकाबले अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में वृद्धि की गति का मंद पड़ना चिंताजनक है। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर सात प्रतिशत से घटकर 2.8 प्रतिशत, खनन क्षेत्र की पांच प्रतिशत से घटकर शून्य से भी नीचे, विनिर्माण क्षेत्र की 7. 6 फीसदी से घटकर 2.5 प्रतिशत और व्यापार, होटल तथा परिवहन क्षेत्र की वृद्धि 11.1 प्रतिशत से घटकर 9.9 प्रतिशत हो गई है। देश के आठ आधारभूत उद्योगों की वृद्धि दर अप्रैल महीने के दौरान 2.2 फीसदी दर्ज की गई। विकास दरों में गिरावट को लेकर सरकार अपनी नाकामी छिपाने का प्रयास कर रही है। हकीकत यह है कि विकास दरों में गिरावट बाहरी कारणों से नहीं, बल्कि घरेलू कारणों से आई है। बेकाबू महंगाई के साथ ब्याज दरों का उच्चतम स्तर पर होना इस गिरावट का मुख्य कारण है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि विकास दर में गिरावट से न केवल रोजगार के अवसरों में कमी आएगी, बल्कि इससे पहले से ही बेकाबू महंगाई के और बढ़ने का खतरा है, किंतु कांग्रेस जनसरोकारों से बेफिक्र है। रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, कांग्रेस की वर्तमान मानसिकता ऐसी ही है। ■

सा. दै. जागरण

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि विकास दर में गिरावट से न केवल रोजगार के अवसरों में कमी आएगी, बल्कि इससे पहले से ही बेकाबू महंगाई के और बढ़ने का खतरा है, किंतु कांग्रेस जनसरोकारों से बेफिक्र है। रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, कांग्रेस की वर्तमान मानसिकता ऐसी ही है।

पृष्ठ 18 का शेष...

इसे साधने के लिए, संविधान का अनुच्छेद 324 में, जो भारत के निर्वाचन आयोग से जुड़ा है, यथोचित संशोधित किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 324(2) के वाक्यांश से पता चलता है कि इसके लिए किसी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इसे सामान्य विधि से पूरा किया जा सकता है।

अगले वर्ष, एक और संवैधानिक संस्था–सीएजी में रिक्त स्थान बन जाएगा। मैं पहले से ही सुझाव देना चाहूंगा कि इस मामले में भी यथासम्भव सर्वोत्कृष्ट उम्मीदवार का चयन करने के लिए एक व्यापक आधार वाले कालेजियम को ही नियुक्ति करने के लिए अधिकार दिया जाए।

मुझे आशा है कि आप मेरे सुझाव को स्वीकार करेंगे और तेजी से इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

सादर,

Hkonh;

¼ykyÑ".k vkMok.kh½

स्वच्छ दामन पर काला दाग

& ,- l;çdk'k

कोयला खदानों के आवंटन में घोटाले के आरोपों को महीनों अनसुना करने के बाद अब मनमोहन सिंह अपने आलोचकों को यह कहकर शांत करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी व्यक्तिगत साख संदेह से परे है, इस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। इसी आधार पर वह संप्रग सरकार के कार्यकाल में हुए कोयला आवंटन और खासतौर पर उस कालखंड में हुए आवंटन की विश्वसनीय, स्वतंत्र जांच कराने से इन्कार कर रहे हैं जब कोयला मंत्रालय उनके पास था।

कोयला आवंटन घोटाला कुछ माह पहले तब प्रकाश में आया था, जब नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में इस मुद्दे का खुलासा हुआ था। कैग की इस रिपोर्ट से पहले तक हर कोई यही मानता था कि 2जी ही तमाम घोटालों का बाप है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि निजी क्षेत्र पर .पा के कारण सरकारी खजाने को 10.7 लाख करोड़ रुपये की चपत लगी है। आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच हुए कोयला खदानों के आवंटन में कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाते हुए 10.7 लाख करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाया गया। ध्यान दें कि यह रकम 1.76 लाख करोड़ के 2जी घोटाले से सात गुना अधिक है।

महीनों से इस मुद्दे से कन्नी काटते आ रहे प्रधानमंत्री को तब जवाब देने को मजबूर होना ही पड़ा जब टीम अन्ना ने 2006–09 में हुए कोयला घोटाले का सीधा जिम्मेदार प्रधानमंत्री को ठहरा दिया। इससे पहले तक 10 लाख करोड़ से अधिक के नुकसान के आरोपों पर सरकार कैग, मीडिया और इस मुद्दे को उठाने वालों को ही उलटा घेरने लगती थी। जिस प्रकार 2जी स्पेक्ट्रम में कपिल सिब्बल ने सरकार को होने वाले आर्थिक नुकसान से इन्कार किया था उसी प्रकार कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जयसवाल ने कैग रिपोर्ट को अनुमानों और कल्पना पर आधारित बताया।

प्रधानमंत्री की छवि को लेकर अंधभक्तों के अलावा अब सबने यह बात स्वीकार कर ली है कि जो किसी समय लिली का सफेद फूल था, अब काले कोयले में तब्दील हो गया है। कोयला आवंटन में हुए घोटाला प्रधानमंत्री के चेहरे पर मुस्कान नहीं ला पाएगा। इसके बजाय यह उनकी सरकार की छवि को और दागदार ही करेगा।

टीम अन्ना ने कोयला खदानों की बिक्री की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की, क्योंकि कोयला मंत्रालय 2006 से 2009 तक सीधे प्रधानमंत्री के अधीन था, इसलिए टीम अन्ना ने निजी कंपनियों को भारी लाभ पहुंचाने के लिए सीधे मनमोहन सिंह को जिम्मेदार ठहराया। इसके जवाब में मनमोहन सिंह ने संवैधानिक प्रक्रिया की आड़ लेते हुए दावा किया कि सरकार को कैग की आधिकारिक रिपोर्ट नहीं मिली है। जैसे ही रिपोर्ट मिलेगी, सरकार लोकलेखा समिति को तथ्यात्मक जवाब भेजेगी। इस बारे में कोयला मंत्रालय ने दावा किया कि कोयले की खदानें निजी कंपनियों को केवल उपयोग विशेष के लिए कैप्टिव उद्देश्य से दी गई हैं, न कि इन्हें बेचा गया है इसलिए इन खदानों को कोयले के बाजार मूल्य से जोड़कर देखने का सवाल ही नहीं उठता। मंत्रालय के अनुसार देश को उच्च विकास के रास्ते पर आगे ले जाने, ऊर्जा, स्टील और सीमेंट क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए आवंटन में जल्दबाजी जरूरी हो गई थी। अगर कोयले की खदानों का आवंटन न किया जाता तो इससे कोयले का आयात करना पड़ता। जाहिर है इसका खामियाजा विदेशी मुद्रा भंडार को उठाना पड़ता, जिससे देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती।

कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी कोयला मंत्रालय के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि कोयला खदानों के आवंटन को केंद्र सरकार ने कभी कमाई का जरिया नहीं माना। सरकार की मंशा तो तीव्र आर्थिक विकास के लिए ढांचागत सुविधाओं का विकास करना था इसलिए अधिक से अधिक आय अर्जित करने का सवाल ही नहीं उठता। अगर केंद्र सरकार की दलीलें सही हैं तो वह स्वतंत्र और गहन जांच से इन्कार क्यों कर रही है? यहां सवाल यह भी उठता है कि अपने आचरण को संदेह से परे बताकर क्या प्रधानमंत्री यह बताना चाहते हैं कि कोयला खदानों के आवंटन में उनकी भूमिका की जांच नहीं होनी चाहिए? ठीक इसी कारण देश को एक मजबूत और स्वतंत्र

शेष पृष्ठ 21 पर

नीति, नीयत और नेतृत्व

& çks- vk'kh"k cksl

#पये की गिरती कीमत और बिगड़ते वैश्विक माहौल के बीच जीडीपी के खराब आंकड़े बहुत निराश करने वाले हैं। इससे तो यही जाहिर होता है कि संप्रग–2 का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह न तो सरकार को ठीक से चला पा रहे हैं और न ही अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला पा रहे हैं। यह स्थिति किसी के हित में नहीं–न देश के और न ही सरकार के। इसलिए बेहतर यही होगा कि सरकार स्थिति की गंभीरता पर ठीक तरह से विचार करे और तात्कालिक उपायों तक सीमित रहने के बजाय दीर्घकालिक कदमों पर जोर दे। देश के बिगड़ते आर्थिक हालात को सुधारने और बढ़ते राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकारी खर्चो में कटौती का अभियान छेड़ने का जो फैसला लिया गया है वह हास्यास्पद है। पांच सितारा होटलों में सम्मेलन–बैठकें न करने, विदेश यात्राएं कम करने जैसे फैसलों से क्या होगा? जब जरूरत व्यापक बदलावों और बड़े नीतिगत फैसलों की है तो सरकार छोटे–मोटे कदम उठा रही है। दरअसल सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि वास्तव में किया क्या जाए? यदि सरकार सोच रही है कि इस तरह के कदमों से राजस्व घाटे को कम किया जा सकता है तो यह उसकी भूल है। सरकार खर्चे को कम करने के नाम पर कुछ वैसा ही खेल कर रही है जैसा महंगाई के मोर्चे पर उसने किया। महंगाई रोकने के तमाम उपाय और दावे खोखले साबित हुए और सरकार को भी अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी। इसलिए कहीं ऐसा न हो कि 2014 का चुनाव आने तक सरकार को एक बार और मुंह की खानी पड़े और स्वीकार करना पड़े कि वह देश को चला पाने में नाकाम रही।

अब यह भी प्रश्न उठने लगे हैं कि क्या देश 1990 वाली स्थिति में वापस लौट रहा है और क्या हम हिंदू विकास दर की गिरफ्त में फंस रहे हैं? इसका सटीक उत्तर दे पाना बहुत आसान नहीं, फिर भी भविष्य के प्रति मैं निराशावादी नहीं हूं। मेरे आशावाद की वजह सरकार नहीं, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षमता है। 1989 में जब देश बुरे दौर से गुजर रहा था तो मेरी मुलाकात प्रसिद्ध उद्योगपति जेआरडी टाटा से हुई। मैंने उनसे भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेकर सवाल रखे तो उनका जवाब था कि मैं अल्पसमय के लिए निराशावादी हूं, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से आशावादी हूं और मुझे एक बेहतर भारत की तस्वीर नजर आती है। उनकी बात सच साबित हुई, लेकिन ऐसा तभी हो सका जब सरकार बदली, नेतृत्व बदला और हमारी आर्थिक नीतियां बदलीं। आज भी स्थिति कुछ वैसी ही दिख रही है। मजाक में कहा जा रहा है कि वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी सरकार के लिए दर्जी की भूमिका निभा रहे हैं और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए जो भी कपड़े सिलते हैं वह उन पर फिट नहीं बैठते। आशय यही है कि नेतृत्व ठीक से नहीं हो रहा। यही बात घपलों–घोटालों को लेकर भी है। व्यक्तिगत ईमानदारी की अपनी छवि के साथ प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार को फलने–फूलने का मौका देते रहे, हालांकि अब उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति निराशाजनक है और सरकार अपनी नाकामी का ठीकरा किसी और के सिर फोड़ना चाहती है।

रुपये की गिरती कीमत और बिगड़ते वैश्विक माहौल के बीच जीडीपी के खराब आंकड़े बहुत निराश करने वाले हैं। इससे तो यही जाहिर होता है कि संप्रग–2 का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह न तो सरकार को ठीक से चला पा रहे हैं और न ही अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला पा रहे हैं। यह स्थिति किसी के हित में नहीं–न देश के और न ही सरकार के।

जहां तक हिंदू विकास दर की बात है तो यह अर्थव्यवस्था की स्थायी सुस्त रफ्तार को दर्शाती है, परंतु आज ऐसी स्थिति नहीं है। अर्थव्यवस्था में गिरावट की वजह नीति विषयक मामलों में निर्णयहीनता, सुशासन का अभाव और सरकार चला पाने की विफलता है। सरकार ग्रीस संकट का हौवा खड़ा कर रही है, जबकि खुद वह कोई

निर्णय नहीं ले रही। वैश्विक संकट का बहाना ठीक नहीं। यदि सरकार रुपये की गिरती कीमत को नहीं थामती है तो स्थिति बहुत बिगड़ सकती है। हमें अपने उपभोग का ज्यादातर तेल बाहर से मंगाना पड़ता है, रक्षा उपकरणों के मामलों में भी विदेशी निर्भरता ज्यादा है, इसलिए आयात का खर्च बढ़ता जाएगा। यह व्यापार घाटा बढ़ने और चालू खाते के भुगतान संकट के रूप में सामने आएगा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि महंगाई अभी भी उच्च स्तर पर बनी हुई है, जिस कारण रिजर्व बैंक के तमाम प्रयास नाकाम हो रहे हैं और घरेलू मांग बढ़ाए नहीं बढ़ रही। महंगाई बढ़ने की एक बड़ी वजह भ्रष्टाचार भी है और इस संबंध में अन्ना हजारे का आंदोलन एक चेतावनी है, जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए।

जीडीपी दर में गिरावट से सरकार की आय कम होगी, जिससे राजकोष पर भार बढ़ेगा। साफ है कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, दोनों ही मोर्चों पर आने वाले समय में दबाव बढ़ता जाएगा। विश्व बाजार में खराब होती विश्वसनीयता के कारण विदेशी निवेशक भी दूरी बना रहे हैं। ऐसे में सरकार इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग सिस्टम बनाने और विनिर्माण क्षेत्र में बड़े सुधार जैसी बातें कह रही है ताकि अच्छे संकेत दिए जा सकें, लेकिन यह काफी नहीं, क्योंकि यह समय कुछ करने का है, कहने का नहीं। पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के बाद अब डीजल और एलपीजी के दामों में वृद्धि का माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन हम भूल रहे हैं कि आम आदमी अब और अधिक बोझ उठा पाने में सक्षम नहीं। आम आदमी की जरूरत की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। सरकार को इस तरफ बिना किसी देरी के ध्यान देना होगा। हमारे पास पर्याप्त गेहूं का उत्पादन हुआ है, लेकिन समस्या यह है कि उसे रखने के लिए गोदाम नहीं हैं। यह किसकी विफलता है? कुछ ऐसा ही हाल दूसरी चीजों का भी है। सरकार वैश्विक मंदी की बात कर रही है, लेकिन कोई यह नहीं बता रहा कि भारत कैसे बचेगा और आम आदमी के हितों की रक्षा कैसे होगी? योजना आयोग ने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए एक और समिति बना दी है, लेकिन आम चीजों और खाद्यान्न वस्तुओं की बढ़ रही महंगाई पर वह मौन है।

केंद्र से अच्छा तो राच्य सरकारें काम कर रही हैं। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के मुताबिक अब तरक्की के रिपोर्ट कार्ड में बिहार अव्वल है। पिछड़े माने जाने वाले राच्य तक बेहतर कर रहे है, लेकिन केंद्र सरकार पंगु है। राज्यवार विकास की समीक्षा की जानी चाहिए और कमियों को दूर करने के लिए मिलजुलकर कदम उठाने चाहिए। सामूहिक नेतृत्व और सामूहिक भावना से काम करने की आवश्यकता है, न कि आंकड़ेबाजी का खेल खेलने की। हमारे पास एक बड़ी शिक्षित युवा आबादी है, योग्य और प्रतिभावान विशेषज्ञ हैं, सशक्त सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और मीडिया है, यदि नहीं है तो केवल और केवल ईमानदार इच्छाशक्ति वाली सरकार। सरकार में न तो नेतृत्व बचा है, न उसकी अच्छी नीयत है और न ही उसके पास दीर्घकालिक नीतियां हैं।■

सा. दै. जागरण

पृष्ठ 19 का शेष...

लोकपाल की आवश्यकता है। अगर आज इस प्रकार की संस्था मौजूद होती तो प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत की जांच एक ऐसी एजेंसी करती जो खुद प्रधानमंत्री या सरकार के अंगूठे के नीचे नहीं है। ऐसी संस्था बड़ी आसानी व सहजता से प्रधानमंत्री को दोषी ठहरा सकती है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ने सीबीआइ को कोयला घोटाले की शुरुआती जांच करने को कहा है, किंतु यह देखते हुए कि आज सरकार किस प्रकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है और पूरे देश का इससे भरोसा उठ गया है, इस जांच के नतीजे को लेकर आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता। प्रधानमंत्री को स्वतंत्र जांच के लिए तुरंत हामी भरनी चाहिए, ताकि उनके और कोयला मंत्रालय के दावों का परीक्षण हो सके। 2012 में प्रधानमंत्री के जोरदार विरोध का कोई खास मतलब इसलिए नहीं रह गया कि पिछले तीन वर्षो में बहुत कुछ घट चुका है। तब मनमोहन सिंह की छवि श्वेत लिली और कीचड़ में खिले कमल की थी। तीन साल पहले यानी संप्रग सरकार के दूसरे कार्यकाल के शुरू होते ही उनकी छवि तार–तार होनी शुरू हो गई थी। यद्यपि अब तक भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई सीधा आरोप नहीं लगा है, फिर भी उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जा रहा है जो भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार का नेतृत्व कर रहा है। अब इस छवि पर लगे दाग छूटना बेहद कठिन हो गया है। प्रधानमंत्री की छवि को लेकर अंधभक्तों के अलावा अब सबने यह बात स्वीकार कर ली है कि जो किसी समय लिली का सफेद फूल था, अब काले कोयले में तब्दील हो गया है। कोयला आवंटन में हुए घोटाला प्रधानमंत्री के चेहरे पर मुस्कान नहीं ला पाएगा। इसके बजाय यह उनकी सरकार की छवि को और दागदार ही करेगा। ■

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं) *सा. दै. जागरण*

भाजपा सुशासन, विकास और राष्ट्रवाद के दर्शन को लेकर राष्ट्र की नियति बदल कर रहेगी : गडकरी

&gekj; lokknnkrk }kjk

Xत 10 मई को भारतीय जनता पार्टी का पांचवां सम्मेलन थमरई संगमाम, मदुरई में आरम्भ हुआ जिसमें भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी से अनुरोध किया गया कि वे पार्टी के विकास को उस राह पर ले जाएं जिससे हमारी पार्टी तमिलनाडु में प्रमुख द्रविड पार्टियों के स्थान पर शक्तिशाली बन कर उनका विकल्प बन जाए।

इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष ने अपने सम्बोधन में कहा कि भाजपा सुशासन और विकास के अपने एजेण्डे पर चलकर और राष्ट्रवाद को अपना दर्शन मानते हुए इतनी क्षमता रखती है कि वह राज्य और राष्ट्र की नियति को बदल सकती है। उन्हें इस बात का विश्वास है कि भाजपा इस सम्मेलन के बाद भाजपा तमिलनाडु में शक्तिशाली होगी और संसद तथा राज्यविधान सभा में प्रतिनिधित्व करने में समर्थ होगी। उन्होंने कहा कि 2014 में होने वाले लोकसभा चुनावों में राज्य को प्रमुख लाभ प्राप्त होगा।

श्री गडकरी ने संप्रग सरकार पर श्रीलंका में नरसंहार रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया। यूपीए का घटक द्रविड मुनेत्र कजगम भी तमिलों की रक्षा नहीं कर पाया है। भाजपा चाहती है कि श्रीलंका में तमिलों के साथ अत्याचार बंद हो और वे पूरी गरिमा से वहां रह सके।

पूर्व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि समय आ गया है कि लोगों को बताया जाए कि सरकार में परिवर्तन लाना अत्यंत आवश्यक है। श्री नायडू ने दावा किया कि अब देश को भाजपा की अत्यंत आवश्यकता है। यही वह पार्टी है जो पूरी तरह संगठित है, जबकि अन्य पार्टियां बंट चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मदुरई सम्मेलन तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ेगा।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री पोन. राधाकृष्णन ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि तमिलनाडु की दो प्रमुख द्रविड़ पार्टियों का विकल्प बनने की चुनौती को स्वीकार करें। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सम्मेलन राजनीति में एक नया मोड ला कर रहेगा।

भाजपा राष्ट्रीय सचिव श्री पी. मुरलीधर राव ने कहा कि पार्टी का उद्देश्य अगला सम्मेलन चेन्नैई में करना होगा। यदि भाजपा तमिलनाडु में शक्तिशाली बन जाती है तो विभाजनकारी ताकतों द्वारा किए जाने वाले बम के खतरों और विस्फोटों की चुनौती समाप्त हो जाएगी। भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जो तमिल गौरव, संस्कृति और भाषा की रक्षा कर सकती है।

श्री मुरलीधर राव ने कहा कि भाजपा के दो दिवसीय थमरई संगमाम पांचवां सम्मेलन ने तमिलनाडु राजनैतिक कार्रवाई की योजना तैयार की है। इस बैठक से राजनैतिक एजेण्डे की तैयारी से भाजपा तमिलनाडु की राजनीति में ठोस भूमिका निर्वाह कर सकेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना में राज्य के सभी मुद्दों को शामिल किया गया है जिसमें मछुआरों, श्रीलंका के तमिलों तथा

शेष पृष्ठ 29 पर

गंगा को प्रदूषणमुक्त बनाने का संकल्प

गत 24 एवं 25 मई को मुंबई में आयोजित भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में 'पवित्र गंगा की सुरक्षा और प्रदूषण मुक्ति' को लेकर मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती ने एक वक्तव्य प्रस्तुत किया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने के बावजूद उसे प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। भाजपा का मानना है कि गंगा की सुरक्षा और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इसे मिशन मानकर काम करने की जरूरत है।

Hkkरतीय जनता पार्टी गंगा नदी में उच्च स्तर के भयावह प्रदूषण पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करती है। गंगा के प्राकृतिक प्रवाह में अनेक बाधायें उत्पन्न करके इसके प्रदूषण को और अधिक बदतर बना दिया गया है। अन्नतकाल से भारत की संस्कृति और सभ्यता की पहचान और सबसे पवित्र प्रतीक के रूप में जिस गंगा को भारत की अनन्त पीढ़ियों द्वारा श्रद्धाभाव से देखा जाता रहा है, उस पवित्र नदी के प्राकृतिक जीवन को विकास की दोषपूर्ण अवधारणों ने गहरे संकट में डाल दिया है।

पिछले कई वर्षों से धार्मिक नेताओं, पर्यावरणविदों और सामाजिक रूप से सक्रिय कार्यकर्ताओं ने गंगा के प्रदूषण के विभिन्न मुद्दों पर लगातार सक्रिय प्रयास किया है, परन्तु गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (जिसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री है) द्वारा इस संदर्भ में कोई व्यावहारिक और स्थाई समाधान खोजने में असफल रहने पर भाजपा गहरा दुःख व्यक्त करती है।

हम भारत के लोग सभी नदियों और जल स्रोतों को पवित्र मानकर उनके प्रति श्रद्धाभाव रखते हैं। यह इस बात से स्पष्ट होता है कि हिमालय में गंगोत्री, जहां से गंगा का जन्म होता है और बंगाल में गंगासागर जहां आकर गंगा समुद्र में मिलती है, दोनों ही स्थान भारत में पवित्र तीर्थ स्थल रूप में माने जाते हैं। गंगा के किनारे स्थित अन्य पवित्र स्थल ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग एवं वाराणसी पवित्र शहर है।

'गंगा जल' न केवल लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़े रहने के कारण पवित्र माना जाता है अपितु वैज्ञानिक अनुसंधानों ने भी इसके अद्वितीय चरित्र को प्रमाणित किया है। गंगा भारत के 11 राज्यों की 40 प्रतिशत जनसंख्या को जल भी उपलब्ध कराती है।

यह बड़ा दुःखद है कि जो गंगा भारत की सभ्यता को हजारों वर्षों से पोषित कर रही है उसी गंगा के अस्तित्व की सुरक्षा की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

अनियोजित सभ्यता और असंतुलित औद्योगीकरण ने नदी में प्रदूषण के स्तर को जहरीला बना दिया है। एक के बाद एक किए गए अध्ययन यह बताते है कि बायोकेमिकल आक्सीजन डिमांड और केलिफार्म, जो गंगा के प्रदूषण को मापने के साधन है, के आधार पर गंगा में प्रदूषण उच्च स्तर पर माना गया है।

जिन राज्यों से गंगा बहती है वहां नदी के प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग बीमारी से मृत्यु के शिकार हो रहे हैं।

अप्रैल में संपन्न गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की बैठक में स्वयं प्रधानमंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया था कि गंगा में समाहित होने वाले 290 करोड़ लीटर गंदे पानी में से केवल 110 करोड़ लीटर का ही परिशोधन किया जाता है। यह लगभग उस गंगा एक्शन प्लान की पूर्ण असफलता को दर्शाता है जिसे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने 1985 में मंगल ध्वनि के साथ प्रारम्भ किया था और जिस पर अभी तक हजारों करोड़ों रुपये बेकार ही खर्च किये जा चुके हैं।

यह बड़ी भयावह स्थिति है कि प्रयाग में जहां पूरे विश्व

और देश से हजारों श्रद्धालु कुंभ के लिए आते हैं वहां बहुत ही न्यून मात्रा में शुद्ध जल पाया जाता है। यह कम चिंता की बात नहीं है कि बांधों द्वारा उत्पन्न किये गये विचलन और बाधाओं के कारण नदी का बहुत बड़ा फैलाव सूखा रहता है।

निर्मल गंगा, अविरल गंगा

भाजपा यह मानती है कि गंगा की यह स्थिति पूर्णतया अस्वीकार्य है। हम यह मानते हैं कि सरकारों (केन्द्र, राज्य और स्थानीय) और लोगों का यह पवित्र राष्ट्रीय कर्त्तव्य है कि वे गंगा की पवित्रता और इसके अविरल प्राकृतिक प्रवाह को अक्षुण्ण बनाये रखे और ऐसा भारत की अन्य नदियों के साथ भी व्यवहार किया जाये। निर्मल और अविरल गंगा के प्रवाह को बनाये रखने के लिए प्रकट की जाने वाली प्रतिबद्धता का यही अर्थ है।

यहां यह आवश्यक है कि हम याद करें कि 'अविरल गंगा' के लिए पहली बार आवाज महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने उठाई थी, जब ब्रिटिश सरकार ने हरिद्वार के पास गंगा के प्रवाह की दिशा को बदलने को प्रयास किया था। मालवीय जी द्वारा चलाये गये व्यापक प्रचार के कारण साम्राज्यवादियों को हिन्दू समुदाय की भावना का सम्मान करना पड़ा और 1916 में अविरल गंगा के प्रवाह को बनाये रखने की गारंटी दी गई।

भाजपा मालवीय जी की इस विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लेती है। जिनकी जन्मदिन का 150वीं वर्षगांठ पिछले वर्ष मनायी गई।

अविरल गंगा से यह आशय नहीं है कि पूरी नदी पर कहीं भी बांध नहीं होना चाहिए। विशेषज्ञों की दृढ़ मान्यता है कि सिंचाई और ऊर्जा उत्पादन के लिए बांध बनाने के बाद भी गंगा के प्राकृतिक प्रवाह को बाधारहित और अविरल बनाया रखा जा सकता है।

यह तब और आसान हो सकता है जब छोटे बांधों की संरचना इस प्रकार बनायी जाये कि इन छोटे बांधों से उतनी ही ऊर्जा प्राप्त की जा सके जितनी की बड़े बांधों से प्राप्त करने का दावा किया जाता है। गंगा की सुरक्षा और प्रदूषण मुक्त बनाने की दृष्टि से पार्टी की ठोस प्रतिबद्धता को कार्यरूप में परिणित करने के लिए, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी यह संकल्प लेती है कि :

1. गंगा को निर्मल और अविरल बनाए रखने के लिए गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण को विशिष्ट और समयबद्ध कार्य करने का सुनिश्चित दायित्व दिया जाना चाहिए। चूंकि गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया जाता है इसीलिए राज्यों में गंगा नदी के तट पर स्थित विभिन्न शहरों के विकास/ऊर्जा/वित्तीय आवश्यकताओं की आपूर्ति का कार्य केन्द्र सरकार द्वारा किया जाना चाहिए।
2. प्रदूषण को अनुमत बनाये रहने देने और फिर बाद में समाधान ढूढ़ने के बजाय जो कि पूरी तरह असंगत और अवैज्ञानिक सोच है, केन्द्र, राज्य सरकारों और स्थानीय सरकारों द्वारा औद्योगिक गंदे पानी को गंगा में मिलने से रोकने के लिए संयुक्त रूप से जारी किया गया निर्देश बनाना चाहिए। औद्योगिक इकाइयों को इस योग्य बनाया जाना चाहिए कि वह प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण साधन अपनाये। नियमों को तोड़ने वालों पर कार्रवाई करने के लिए एक सख्त दण्डात्मक कानून का सहारा लिया जाना चाहिए।
3. राज्य और स्थानीय प्रशासन को नालियों के गंदे पानी के निपटान और गंदे पानी को उपचारित करने के प्लांट लगाने में सहायता प्रदान की जानी चाहिए। यह कार्य ग्राम सभा और स्थानीय सिविल निकायों द्वारा विकेन्द्रीयकरण के द्वारा बेहतर तरीके से किया जा सकता है।
4. यह अनुभव रहा है कि गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण अपने उद्देश्य में पूरी तरह असफल रहा है, भाजपा यह मांग करती है कि गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के लिए संसद द्वारा कानून बनाकर प्राधिकरण को सशक्त और दण्ड देने के लिये प्राधिकृत किया जाय। यह कानून यह घोषणा करे कि गंगा भारत की अमूल्य राष्ट्रीय धरोहर है।
5. गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण द्वारा लागू किये गये निर्णयों की पर्यवेक्षण के लिए कैग जैसी कोई स्वायत्त संविधानिक संस्था होनी चाहिए।
6. भाजपा यह मानती है कि गंगा की सुरक्षा और प्रदूषण मुक्त बनाने का कार्य राष्ट्रीय मिशन के रूप में होना चाहिए। इस कार्य के लिए सभी लोगों के सहयोग और उत्साही सहभागिता की जरूरत है। बड़ी संख्या में धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण संगठन इस मिशन में पहले से ही सक्रिय हैं। भाजपा उनके प्रयासों की सराहना करती है हम उनसभी संगठनों को सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध ओर तत्पर है और हम अन्य राजनीतिक पार्टियों और उनकी सरकारों से भी इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एजेंडा में सहयोग के लिए तत्पर है।
7. भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी निर्मल और अविरल गंगा की मांग को व्यापक स्तर पर जन समर्थन प्राप्त करने के लिए वृहद जनजागरण अभियान चलाने का संकल्प लेती है। ■

यूपीए की शासन-पद्धति का संकट और विश्वसनीयता की कमी ने पूरे राष्ट्र को हिला दिया

गत 25 मई को मुम्बई में आयोजित भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली ने राजनैतिक प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु रखे थे। हम अपने सुधी पाठकों के लिए ये बिन्दु प्रकाशित कर रहे हैं:–

यूपीए–II ने निकृष्टतम शासन हमारे सामने पेश किया है। पारम्परिक रूप से भारत ऐसा देश है जो लचीलापन रखकर हर वर्ग को मजबूत बनाने की कोशिश करता है। किन्तु, शासन–पद्धति का वर्तमान संकट और विश्वसनीयता की कमी ने पूरे राष्ट्र की विश्वसनीयता को हिला कर रख दिया है। आज, निराशा और लाचारी का दौर चल रहा है। यूपीए–II राजनैतिक प्रबंधन और आर्थिक निर्णय लेने में एक नए निम्न स्तर पर पहुंच गई है; सच तो यह है कि आज न तो कोई आर्थिक प्रबंधन दिखाई पड़ता है, न ही कोई राजनैतिक दिशा दिखाई पड़ती है।

आज नेतृत्व का संकट पैदा हो गया है। सरकार का मुखिया न तो पार्टी या देश का स्वाभाविक नेता रह गया है। भारी स्तर पर पूंजी और निवेश खत्म होता जा रहा है। वर्षों से मुद्रास्फीति नियंत्रण से बाहर है। कृषि की अधिक पैदावार और कमी दोनों ही प्रबंधन का संकट बन गई हैं। टेलीकॉम, हाईवे, रियल एस्टेट आदि की सफल गाथाएं भी घोटालों में परिवर्तित हैं। कोई भी राष्ट्र अपनी सफलता का विनाश सहन नहीं कर सकता है। इन सबसे हमारी आर्थिक गतिविधियां कम हो गई हैं और इससे बेरोजगारी बढ़ेगी और राजस्व की हानि होगी।

यूपीए का राजनैतिक प्रबंधन भी देश के लिए उतना ही विनाशकारी है। यूपीए के सहयोगी दल बुरी तरह से असंतुष्ट हैं। वे घोषणाएं करने में तो आगे हैं, परन्तु प्रहार करने में पीछे हैं। बीएसपी और एसपी जैसे दलों पर सीबीआई का दबाव डाल कर उन्हें दबे रहने पर मजबूर कर रहा है। माओवाद निरन्तर बढ़ता चला रहा है। सरकार के पास इनसे निपटने के लिए कोई योजना नहीं है। इसकी बजाए कि जम्मू और कश्मीर भारत में पूर्ण रूप से विलय हो जाए, वार्ताकारों की रिपोर्ट ने विपरीत प्रक्रिया की शुरूआत कर दी है।

यूपीए गवर्नेंस आज घमंडी बनकर सामने आ रही है, सीबीआई का दुरूपयोग, विपक्ष या फिर अपने सहयोगी दलों के साथ परामर्श, फेडरेलिज्म पर प्रहार, गैर–कांग्रेसी सरकारों के साथ भेदभाव– ये सभी बातें सरकार के कामकाज का नियमित हिस्सा बन गई हैं। इस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप निरन्तर बढ़ते चले जा रहे हैं। यह स्थिति एक चुनौती पेश करती है और भाजपा के लिए यह एक अवसर है।

- अब भाजपा को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बहाल करने के लिए योजना और दिशा प्रदान के लिए तैयार रहना चाहिए।
- देश में फैले कांग्रेसवाद–विरोधी रूख का लाभ उठाना चाहिए और एनडीए का विस्तार होना चाहिए।
- गवर्नेंस का तीसरा मोर्चा बनाने का अनुभव बार–बार किया जाता है। यह विफल है और इसकी पुनर्स्थापना संभव नहीं है।
- हमें भाजपा को सामंजस्यपूर्ण नैतिक दल बनाना होगा, जो देश को दिशा प्रदान कर सके।
- हमें अपने अंदर से किसी भी प्रकार की उभरने वाली परस्पर–विरोधी बातों से बचना होगा।
- हमने केन्द्र (1998–2004) और राज्यों में उत्कृष्ट शासन प्रदान किया है। हमें अपने सुशासन के एजेण्डा को मजबूत बनाना होगा।■

भाजपा-नीत एनडीए सरकार 2014 के चुनावों में फिर सत्ता में लौटेगी : गडकरी

&gekj: loknnkrk }kjk

Xत 25 मई को मुम्बई में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की समाप्ति के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित एक विशाल रैली को सम्बोधित करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने कहा कि भाजपा–नीत एनडीए 2014 के लोकसभा चुनावों में फिर से सत्ता प्राप्त करेगा क्योंकि कांग्रेस–नीत यूपीए आज बुरी तरह बीमार होकर आईसीयू में दाखिल हो गया है। आज भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जो प्रत्येक समस्या का समाधान कर पाएगी।

श्री गडकरी ने आगे कहा कि सफलता के तीन मंत्र हैं: एनडीए का विस्तार हो, भाजपा के वोटों में 10 प्रतिशत की वृद्धि हो और गरीबों, अल्पसंख्यकों एवं दलितों में जनाधार बनाने का एकजुट प्रयास किया जाए।

राज्य सभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली ने कहा कि आज कांग्रेस नीत यूपीए सरकार नेतृत्वविहीन है जिससे सरकार नीतिगत अपंगता के वश में पहुंच गई है।

उन्होंने कहा कि आए दिन भ्रष्टाचार के नए–नए मामले सामने आ रहे हैं और देश का आम आदमी इसके लिए कांग्रेस को समुचित उत्तर देकर सत्ता से बाहर करेगा।

इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने सम्बोधन में यूपीए पर जोरदार प्रहार किया और कहा कि केन्द्र में उसकी सरकार के पास कोई नेता या नीति है ही नहीं।

श्री मोदी ने कहा कि आखिर कब तक देश को इस सरकार को सत्ता से बाहर जाने का इंतजार करना पड़ेगा। आज की आवश्यकता यही है कि पूरे राष्ट्र को सरकार के खिलाफ एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए और लोगों को सरकार को यह बता देना चाहिए कि वह सत्ता में रहने लायक नहीं है। जितने दिन वह सत्ता में बनी रहेगी, राष्ट्र उतना ही बुरी तरह तबाह होता चला जाएगा।

गुजरात के मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित एनसीटीसी पर गहरा प्रहार करते हुए सरकार की तुलना 'निर्मल बाबा के दरबार' से की। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को इस बात का जवाब देना चाहिए कि रुपए क्यों निरंतर गिरता जा रहा है। मैं इसके पीछे एक गहन षड्यंत्र देखता हूं।

यूपीए–II में दलों के आपसी कलह पर चोट करते हुए उन्होंने कहा कि कभी तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि गठबंधन की कुछ मजबूरियां होती हैं। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपके विदेश मंत्री यूएन में एक–दूसरे देश के नेता का भाषण पढ़ने लगते हैं। क्या यह भी गठबंधन की मजबूरी है?

सरकार–आर्मी चीफ जन. वी.के. सिंह के बीच गतिरोध का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री दोनों ही कांग्रेस से हैं। फिर भी सरकार आर्मी के खिलाफ टकराव में है। यह कैसी मजबूरी है?

श्री मोदी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर यूएस डालर के मुकाबले रूपए में गिरावट का आरोप लगाते हुए उन पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने प्रधानमंत्री से यह भी पूछा कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल की मुद्राएं डालर के मुकाबले क्यों गिरावट की दिशा में नहीं जा रही हैं?

उन्होंने कहा कि ''मैडम सोनिया का कहना है कि वायदों से काम नहीं

चलेगा, कुछ करके दिखाना होगा। इससे पता चलता है कि उनके पास बस वायदे ही वायदे हैं, काम करके दिखाने को कुछ नहीं। इंदिरा गांधी के 'गरीबी हटाओ आंदोलन' से लेकर आज तक उन्होंने बस हमसे वायदे किए हैं, किया कुछ नहीं।

श्री मोदी ने कहा कि गरीबी के खिलाफ चल रहे संघर्ष में 20–सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत एनडीए के राज्य सदा ही पहले पांच राज्यों में खड़े नजर आते हैं। जब मैंने इस मुद्दे पर उनका ध्यान आकर्षित करने लगा तो उन्होंने कांग्रेस सरकारों से अपने टैंक में सुधार लाने को कहने की बजाए रेटिंग की घोषणा करना ही बंद कर दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने उपलब्धियों के अपने रिपोर्ट कार्ड में बताया था कि पहले कृषि की वृद्धि दर 2.25 थी और अब यह 3.25 है, जिसका अर्थ है कि यह 1 प्रतिशत बढ़ी है। न जाने वह किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं।

हमारे गुजरात राज्य ने पिछले दस वर्षों से निरन्तर 11 प्रतिशत कृषि वृद्धि दर उपलब्ध की है और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि उन्होंने यह वृद्धि दर 2. 25 से बढ़ा कर 3.25 कर दी है। यदि कृषि वृद्धि दर की बढ़ोतरी इसी दर से बढ़ी तो देश डूब जाएगा और लोग भूख से मरते रहेंगे। कुछ राज्य काम कर रहे हैं और देश की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं।

यूपीए सरकार का कहना है कि वह 50,000 मै.वा. बिजली पैदा करेगी और इस रिपोर्ट कार्ड में उनका कहना है 30,000 मै.वा. बिजली पैदा की है। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि यदि इस तरह का बिजली उत्पादन होगा तो इसका श्रेय किन राज्यों को दिया जाएगा। यह राज्यों के कठिन परिश्रम का परिणाम है।

एक तरफ तो इस देश में बिजली के बेहद कमी है, परन्तु नीति के अभाव में, कोयला सेक्टर में भ्रष्टाचार के कारण देश के विद्युत संयंत्रों को कोयला नहीं मिल पाता है, जिससे केवल 60 प्रतिशत बिजली का उत्पादन हो पाता है और 40 प्रतिशत बिजली उत्पादन की क्षमता रूकी रह जाती है।

गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से एनसीटीसी बैठक में पूछा था कि नक्सलियों, आतंकवादियों को कहां से हथियार मिलते हैं, जबकि सीमा पर नियंत्रण केन्द्र का होता है? मैंने उनसे एक और भी सवाल पूछा था कि जब आतंकी–पैसा हमारे देश में हवाला से आता है तो इसको रोका क्यों नहीं जाता? मैंने एक तीसरा सवाल भी किया था कि आतंकी देश में घुसपैठिए बन कर घुसते हैं, जबकि नेवी, बीएसएफ आदि सब आपके नियंत्रण में हैं, वे किस प्रकार से घुस पाते हैं? मैंने प्रधानमंत्री से एक और सवाल भी किया था कि भारत सरकार कम्युनिकेशन पर निगरानी रखती है तो केन्द्र क्यों नहीं उस पर ध्यान देता है? एक और सवाल भी पूछा गया कि आज तक एक भी आतंकवादी को किसी विदेशी देश से यहां नहं लाया गया, क्यों? दिल्ली के सुलतानों का इन सवालों के बारे में कोई जवाब नहीं था। आतंकवाद के खिलाफ 'जीरो टालरेंस' अर्थात् जरा भी सहन न किया जाने की जबरदस्त आवश्यकता है। और केन्द्र के सत्ता में बैठ के आज के ये लोग ऐसा नहीं कर सकते।

इनके अलावा भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी जनसमूह को सम्बोधित किया। ■

पृष्ठ 24 का शेष...

तमिलनाडु में विकास और सुशासन के मुद्दे भी शामिल है। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार की राजनीति को बदलने पर भी जोर दिया गया है। सम्मेलन में भाग लेने वालों ने तमिलनाडु की राजनीति को बदलने का संकल्प लिया और राज्य के आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण के लिए काम करने का बीड़ा उठाया।

प्रस्ताव

एक प्रस्ताव पारित कर आग्रह किया गया कि राज्य सरकार को अतिक्रमणकारियों से मंदिर सम्पत्तियों को मुक्त कराने तथा उन पर कब्जा करने वालों से बकाया वसूल करने के लिए एक समयबद्ध सीमा निर्धारित करनी चाहिए। जो मंदिर राज्य में क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़े हैं, उनके नवीनीकरण के लिए तुरंत उपाय करने चाहिए। एक्जीक्यूटिव ने सरकार से तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन द्वारा चलाई जा रही शराब की सभी दुकानों को बंद करने की अपील भी की ताकि लोगों को शराब पीने से मुक्ति मिले और तमिलनाडु राज्य एक लाभकारी राज्य बन सके। यदि सरकार मुफ्त के माल से बचने का प्रयास करे तो राजस्व के लिए 'टास्मैक' की शराब की दुकानों पर निर्भर करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दूसरे प्रस्ताव पारित कर सम्मेलन ने सभी जिलों में चुनावों के लिए दक्ष विकास केन्द्र शुरू करने एवं मदुरई में सिविल सेवाओं के उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के लिए आईएएस अकादमी शुरू करने का भी आह्वान किया। ■

कैग ने उधेड़ी जनविरोधी कांग्रेस सरकार की बखिया

खजाने को 4000 करोड़ का नुकसान

सरकार के विभागों ने खुली लूट कर जनता के हित के लिए प्राप्त रकम को भी दिल्ली सरकार ने खर्च नहीं किया। 2471 मामलों में कैग ने अनेक गम्भीर अनियमितताएं पकड़ी हैं। इनसे सरकार को 2010–11 में 2019 करोड़ रूपए के राजस्व का नुकसान हुआ। टैक्स की कम वसूली और उसका गलत निर्धारण करके बड़े लोगों को सरकार ने जमकर फायदा पहुंचाया और आम जनता के हित के लिए किए जाने वाले कार्यों को जानबूझ कर लटकाया गया।

दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने 7 जून को नई दिल्ली में कहा कि सरकार के विभागों ने खुली लूट कर जनता के हित के लिए प्राप्त रकम को भी दिल्ली सरकार ने खर्च नहीं किया। 2471 मामलों में कैग ने अनेक गम्भीर अनियमितताएं पकड़ी हैं। इनसे सरकार को 2010–11 में 2019 करोड़ रूपए के राजस्व का नुकसान हुआ। टैक्स की कम वसूली और उसका गलत निर्धारण करके बड़े लोगों को सरकार ने जमकर फायदा पहुंचाया और आम जनता के हित के लिए किए जाने वाले कार्यों को जानबूझ कर लटकाया गया।

श्री गुप्ता ने बताया कि सरकार ने सबसे बड़ा नुकसान शहरी विकास को पहुंचाया। इस विभाग के बजट के बकाया एरियर के 96.51 प्रतिशत रकम को खर्च ही नहीं किया गया। यह धनराशि 12659 करोड़ रूपए है।

दिल्ली सरकार ने बिजली कम्पनियों को जमकर फायदा पहुंचाया। उन्हें नियमों को उल्लंघन करके हजारों करोड़ रूपया लोन दिया गया। यह लोन कम्पनियों ने समय पर नहीं लौटाया। इस पर उनसे लगभग 4 करोड़ रूपए हर्जाना वसूला जाना चाहिए था। सरकार ने यह हर्जाना भी बिजली कम्पनियों से जानबूझ कर नहीं वसूला। यही हाल दिल्ली ट्रांसको लि. का रहा। उसने काम में देरी होने पर ठेकेदारों को खुली छूट दी। उनको लगभग एक करोड़ रूपए का अतिरिक्त भुगतान किया और काम में देरी करने पर ठेकेदारों से 83.83 लाख रूपए का हर्जाना भी नहीं वसूला। इन्द्रप्रस्थ पॉवर जैनरेशन कम्पनी लि. ने ठेकेदार को खुली छूट दी। इससे उसे 22.68 लाख रूपए का नुकसान हुआ। घाटे में चल रही डीटीसी को भी सरकार की गलत नीतियों के कारण 33.14 लाख रूपए का नुकसान हुआ।

सीएजी ने कहा है कि भ्रष्टाचार करने के लिए अनेक प्रपंच किए गए। योजनाएं गलत ढंग से बनाई गईं। इससे पीडब्ल्यूडी, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, सूचना एवं प्रसारण निदेशालय, दिल्ली परिवहन निगम, शहरी विकास विभाग को करोड़ों रूपए का घाटा हुआ। आश्चर्य की बात यह है कि सरकार ने एक तरफ विभिन्न मदों में प्राप्त धनराशि को जनहित पर खर्च नहीं किया और दूसरी ओर अपनी गलती से नुकसान हुए हजारों करोड़ रूपए को खातों में हेराफेरी करके सरकार ने बचत दिखाया। 2303.02 करोड़ रूपए की धनराशि को दिल्ली के ढांचागत विकास पर खर्च ही नहीं किया गया। वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन देने के लिए 100 करोड़ रूपए की धनराशि खर्च ही नहीं की गई। दिल्ली जल बोर्ड के 3 सीवरेज़ परियोजनाओं पर काम करने के लिए 250 करोड़ रूपए आवंटित थे। इनमें से 75 प्रतिशत धनराशि खर्च ही नहीं की गई। यदि यह धनराशि खर्च की गई होती तो अनधिकृत कालोनियों के भाग्य बदल जाते। कैग ने सरकार से लगभग हर विभाग की तीखी आलोचना करते हुए कहा है कि जनहित की योजनाओं में भ्रष्टाचार और घपला करने के लिए अनेक प्रकार की जालसाजी सरकार ने की। एक तरफ सरकार विकास योजनाओं पर हजारों करोड़ रूपए खर्च ही नहीं कर पाई और दूसरी ओर घाटे का रोना रोकर उसने जनता पर अनेक नए कर थोंप दिए हैं। सरकार ने पहली बार बैंक्वेट हॉल, जिम, होटलों आदि पर भी 10 प्रतिशत तक लग्जरी टैक्स लगा दिया। इससे अब आम आदमी भी विवाह आदि समारोहों पर भी सरकार को लग्जरी टैक्स देगी। ■